वर्ष 13 • अंक 13 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 2 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

सोने में गिरावट की आहट

अमित शाह पृष्ठ 4

सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे

एक नज़र

एजीआर बकाया का मूल्यांकन इस हफ्ते संभव

सरकार अपने वायदे के अनुसार बड़ी दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परीक्षण जांच इसी सप्ताह शुरू करा सकती है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया एजीआर के अपने स्व-आकलन की प्रक्रिया तेज करे। ऐसा माना जा रहा है कि दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने शुक्रवार शाम को वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक रविंदर टक्कर के साथ हुई बैठक में दूरसंचार विभाग के मत से उन्हें अवगत करा दिया है।

विवाद से विश्वास से तय होगी वेतन वृद्धि, पदोन्नति

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया है कि वह फील्ड अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति को विवाद से विश्वास योजना के तहत किए गए संग्रह में उनके प्रदर्शन से जोड़ेगा। सीबीडीटी के 21 फरवरी को कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि भविष्य में फील्ड अधिकारियों की नियुक्ति में संग्रह के नतीजों की बड़ी भूमिका होगी। विवाद निपटान योजना की घोषणा के तुरंत बाद विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे अवकाश और शनिवार के दिन भी काम करें ताकि जब योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया जाए तो संग्रह के लिहाज से नतीजे जोरदार हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान आयकर मामलों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। पृष्ठ 4

जीएसके विलय से एचयूएल व नेस्ले में बढ़ेगी प्रतिस्पर्द्धा

यूरोप की दो सबसे बड़ी कंपनियों नेस्ले और यूनिलीवर की प्रतिस्पर्धा भारत में फूड के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका कारण पिछले हफ्ते राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के चंडीगढ़ पीठ की तरफ से हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर के विलय की मंजूरी है। एनसीएलटी की मंजूरी से विलय की रिकॉर्ड तारीख और शेयर आवंटन की घोषणा समेत विलय प्रक्रिया की अंतिम बाधा दूर हो गई। सूत्रों ने कहा कि अब कुछ ही हफ्ते की बात है जिसमें पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जीएसके कंज्यूमर के शेयरधारकों को उनके हर शेयर के बदले एचयूएल के 4.39 शेयर मिलेंगे। पृष्ठ 2

श्रम मंत्रालय 8.65 फीसदी ईपीएफ ब्याज के पक्ष में

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज 8.65 प्रतिशत पर बरकरार रखना चाहता है। एक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ अंशधारक हैं। समझा जाता है कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 5 मार्च, 2020 को होने वाली बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर तय करेगा। सूत्र ने कहा कि ईपीएफ पर 2019-20 में ब्याज दर के प्रस्ताव पर सीबीटी की 5 मार्च की बैठक में विचार किया जाएगा।

सरकारी खरीद कोटे का लाभ बुनकर, क्लस्टरों को भी

खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों से अपनी जरूरत की कपड़ों की कम से कम 20 फीसदी खरीद अनिवार्य रूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा संकुलों और पंजीकृत बुनकरों से करने को कहा है। इसे लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 153 में संशोधन किया है।

कोरोना की गिरफ्त में बाजार

कमजोर आर्थिक आंकड़ों और कोरोनावायरस के प्रसार से निवेशकों में घबराहट

समी मोडक और सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 1 मार्च

कोरोनावायरस के कहर से बाजार को फिलहाल राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते शेयर बाजारों का प्रदर्शन दशक में सबसे खराब रहा और आर्थिक आंकड़ों पर भी वायरस का असर दिखने लगा है। चीन में फैक्टरी गतिविधि की वृद्धि में तेज गिरावट दर्ज की गई। चीन के आधिकारिक परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) फरवरी में 35.7 दर्ज किया गया जो जनवरी में 50 अंक पर था। सप्ताहांत में भी चीन और दक्षिण कोरिया में कोरोनावायरस के नए मामले सामने आए, वहीं अमेरिका, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी वायरस की वजह से लोगों के मरने की खबर है।

फर्स्ट ग्लोबल के संस्थापक और वाइस चेयरमैन शंकर शर्मा ने कहा, 'बाजार के लिए यह कठिन समय है। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी पड़ सकता है।' अधिकांश वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी जा रही है और हालिया उच्च स्तर से करीब 10 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो आने वाले महीनों में यह वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। ऐसा होने पर बाजारों में 20 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के समूह प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल ने कहा, 'कोरोनावायरस का दुनिया भर में तेजी से प्रसार हो रहा है और बाजार को डर है कि यह महामारी बन सकता है। अमेरिका और यूरोप में इसके प्रसार होने से वैश्विक मंदी की चिंता बढ़ सकती है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ सकता है और भारत सहित अन्य देशों की आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है।' बीते शुक्रवार को बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी करीब 4 फीसदी लुढ़क गया और 2015 के बाद एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट रही। दोनों सूचकांक मध्य जनवरी के सर्वकालिक उच्च स्तर से करीब 9 फीसदी नीचे आ गया है।

हालांकि बीते समय में बाजार में 10 फीसदी की गिरावट आने के बाद अच्छी वापसी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार तेज सुधार की गुंजाइश काफी कम है क्योंकि कोरोनावायरस का संकट अभी टला नहीं है।

बीते शुक्रवार को भी शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट देखी गई लेकिन बाद में यह 1.4 फीसदी गिरकर बंद हुआ। अमेरिका में 10 वर्षीय ट्रेजरी रिकॉर्ड 1.14 फीसदी पर बंद हुआ। बाजार के भागीदारों का कहना है कि 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल कोरोना को लेकर गंभीर चिंता का संकेत है। भारत की बात करें तो बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत देने वाला वीआईएक्स सूचकांक 31 फीसदी चढ़ गया। ट्रेडरों का कहना है कि बाजार सितंबर के स्तर पर आ सकता है और आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। (शेष पृष्ठ 7 पर)

कोरोना के डर से सहमा बाजार...

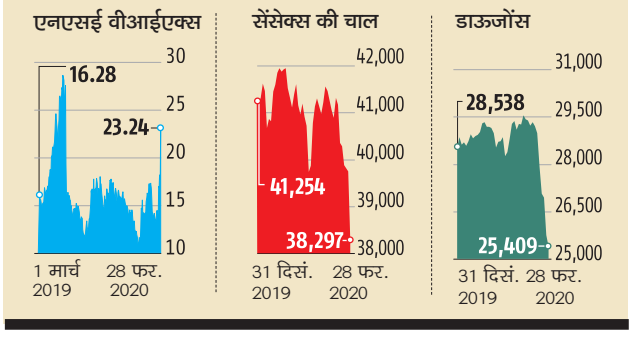

5जी का परीक्षण करेगी जियो, मांगी अनुमति

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 1 मार्च

रिलायंस जियो ने खुद की विकसित प्रौद्योगिकी और डिजाइन पर आधारित 5जी परीक्षण के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय दूरसंचार कंपनी ने 5जी परीक्षण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो उपकरण का डिजाइन और प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए दूसरी कंपनियों को दिया जा सकता है।

जियो ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब उसने अपने 5जी परीक्षण को केवल सैमसंग तक ही सीमित नहीं रखने का फैसला किया है। कंपनी ने इसका दायरा बढ़ाते हुए चीन की दिग्गज कंपनियों हुआवे टेक्नोलॉजिज और एरिक्सन तथा नोकिया नेटवर्क्स को भी शामिल करने का फैसला किया है। इससे पहले चीन की कंपनियों की आक्रामक बोली और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद केवल सैमसंग ही जियो को 4जी सेवाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति करती थी। रिलायंस जियो के एक प्रवक्ता ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

रिलायंस पिछले कुछ समय से चुपचाप शोध एवं विकास डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी क्षमताएं विकसित कर रही है। उदाहरण के लिए पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रैनकोर टेक्नोलॉजिज कोर सॉफ्टवेयर के विकास पर काम कर रही थी जिसमें आधुनिक 4जी नेटवर्क के अनुकूल उत्पाद और सेवाएं बनाना शामिल था। बाद में इसे रिलायंस जियो के साथ मिला दिया गया। 5जी और आईओटी के क्षेत्र में रिलायंस जियो की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रिलायंस ने 2018 में अमेरिका की कंपनी रेडिसिस को 6.7 करोड़ डॉलर में खरीदा था।

रिलायंस का 5जी उपकरण का डिजाइन बनाने का कदम बेहद अहम है क्योंकि दूरसंचार उपकरण डिजाइन और विनिर्माण पर हमेशा विदेशी कंपनियों का दबदबा रहा है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

- स्व-विकसित 5जी तकनीक के परीक्षण के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार
- सफल होने पर दूसरी कंपनी बना सकती है उपकरण
- अभी है विदेशी कंपनियों का दबदबा
- स्वदेश में क्षमता विकास चाहती है सरकार

1.05 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह

फरवरी में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8 फीसदी अधिक है। हालांकि यह इस साल जनवरी की तुलना में कम है। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,05,366 करोड़ रुपये रहा था जिसमें केंद्रीय जीएसटी 20,569 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 27,348 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 48,503 करोड़ रुपये और उपकर 8,947 करोड़ रुपये है। जनवरी के लिए 29 फरवरी तक 83 लाख जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरे गए थे। यह संख्या पिछले महीने भी इतनी ही थी। सरकार ने 22,586 करोड़ रुपये सीजीएसटी और आईजीएसटी से 16,553 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटारा कर लिया है। इस तरह सरकार को नियमित निपटान के बाद फरवरी में 43,155 करोड़ रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी ने 43,901 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। *एजेंसियां*

फरवरी में भी कारों की बिक्री रही सुस्त

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 1 मार्च

वाहन उद्योग की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फरवरी में वाहनों की बिक्री कमजोर रहने के बाद कंपनियां नए उत्सर्जन नियम लागू होने से पहले मौजूदा भंडार समाप्त करने को लेकर भी सतर्क हो गई हैं। वाहन कंपनियों का कहना है कि खरीदार अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और जिनकी कार खरीदने की योजना थी, वे भी आगे नहीं आ रहे हैं।

बैक गियर में कारों की बिक्री

कंपनी	फर. 2020	फर. 2019	% गिरा
मारुति सुजूकी	147,110	148,682	1.11
महिंद्रा ऐंड महिंद्रा	32,476	56,005	42.0
हुंडई	48,910	54,518	10.3

स्रोत : कंपनियां

वाहन कंपनियों का ध्यान नए उत्सर्जन मानक (भारत स्टेज-6) के अनुसार वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित रहा, दूसरी तरफ डीलर नए वाहनों को निकालने के बजाय बीएस-4 वाहनों के मौजूदा भंडार खपाने की पुरजोर कोशिश करते रहे। बीएस-6 उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। कार कंपनियों ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस के कारण चीन में फैक्टरियों में काम प्रभावित होने से कल-पुर्जों की आपूर्ति पर असर हो सकता है, जिससे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस बारे में एमजी मोटर इंडिया में निदेशक (बिक्री) राकेश सिदाना ने कहा, 'कोरोनावायरस के संक्रमण के बाद चीन और यूरोप से आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इससे फरवरी में वाहनों की बिक्री पर असर हुआ है और मार्च में भी कमोबेश हालात ऐसे ही रह सकते हैं। हम स्थिति सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक हालात स्थिर हो जाएंगे।'

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी की बिक्री फरवरी में 1,47,110 तक सिमट कर रह गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,48,682 रही थी। इस तरह, सालाना आधार पर घरेलू बाजार में बिक्री 1.11 प्रतिशत कम रही। हालांकि शुरुआती या छोटे खंड (ऑल्टो, एसप्रेसो) में बिक्री जरूरत 11 प्रतिशत बढ़ी।

डार्ट ने कहा,'कारों की खरीदारी पर मिल रही छूट भी काफी कम हो गई है। एरीना शोरूम में यह कम होकर 15,000 से 20,000 रुपये रह गई है, जबकि नेक्सा शोरूम में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है।' मुंबई स्थित महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) के यात्री वाहनों की बिक्री फरवरी में सालाना आधार पर 58 प्रतिशत कम हो गई। चीन से कल-पुर्जे एवं उपकरण खरीदने में आ रही दिक्कतों के कारण कंपनी ने बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की बिक्री कम हो गई। एमऐंडएम ने फरवरी में 32,476 यात्री वाहन बेचे।

संक्षेप में

30 हजार कर्मियों की भर्ती करेगी कैपजेमिनाई

फ्रांस की प्रौद्योगिकी कंपनी कैपजेमिनाई इस साल भारत में 30,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। भारत में अभी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1,15,000 है। कंपनी ने कहा कि वह भारत में अपनी उपस्थिति का और फायदा उठाना चाहती है। कंपनी के भारत में मुख्य कार्याधिकारी अश्विन यार्डी ने कहा कि ये नियुक्तियां बिल्कुल नए लोगों, अनुभवी पेशवरों और बीच के पदों सहित विभिन्न स्तर पर होंगी। कंपनी के वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की कुल संख्या में आधे भारत में कार्यरत हैं। यार्डी ने कहा, भारत हमारे कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस साल हम कुल मिलाकर 25,000 से 30,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। *भाषा*

कलपुर्जों की कमी से एमजी मोटर की बिक्री प्रभावित

एमजी मोटर इंडिया की बिक्री में फरवरी में भारी गिरावट आई है। चीन और अन्य देशों में कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से कंपनी की कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे उसकी बिक्री में गिरावट आई है। फरवरी में कंपनी की खुदरा बिक्री 1,376 इकाई रही है, जबकि जनवरी में यह 3,130 इकाई रही थी। एमजी मोटर इंडिया के पोर्टफोलियो में दो मॉडल एसयूवी हेक्टर और जेएस ईवी हैं। कंपनी ने पिछले महीने जेएस ईवी की 158 इकाइयां बेचीं। *भाषा*

अब फूड में एचयूएल, नेस्ले के बीच होगा मुकाबला कड़ा

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के एचयूएल में विलय के बाद बाजार हिस्सेदारी के लिए संघर्ष और ज्यादा होने की संभावना

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 1 मार्च

यूरोप को दो सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले और यूनिलीवर की प्रतिस्पर्धा भारत में फूड के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका कारण पिछले हफ्ते नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के चंडीगढ़ पीठ की तरफ से हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर के विलय की मंजूरी है।

एनसीएलटी की मंजूरी से विलय की रिकॉर्ड तारीख और शेयर आवंटन की घोषणा समेत विलय प्रक्रिया की अंतिम बाधा दूर हो गई। सूत्रों ने कहा कि अब कुछ ही हफ्ते की बात है जिसमें पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जीएसके कंज्यूमर के शेयरधारकों को उनके हर शेयर के बदले एचयूएल के 4.39 शेयर मिलेंगे।

विलय के बाद एचयूएल की दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक बनने वाली जीएसके पीएलसी कंपनी में अपनी 5.7 फीसदी शेयरधारिता भुना सकती है। लेकिन प्रस्तावित विनिवेश पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जो ब्लॉक डील के जरिए हो सकती है। जीएसके कंज्यूमर शुक्रवार को 9,444.9 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। एचयूएल और नेस्ले इंडिया का बंद भाव क्रमश: बीएसई पर 2,174.90 रुपये और 15,770.55 रुपये रहा।

जीएसके कंज्यूमर के एचयूएल में विलय से एचयूएल को नेस्ले के साथ राजस्व का अंतर घटाने में मदद मिलेगी। एचयूएल का फूड व बेवरिज कारोबार (जीएसके कंज्यूमर के राजस्व समेत) 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा और यह कहना है कंपनी पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-19 के उनके वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक है। दोनों कंपनियों ने अभी वित्त वर्ष 2020 के नतीजे घोषित नहीं किए हैं।

कैलेंडर वर्ष 2019 में नेस्ले का कारोबार 12,369 करोड़ रुपये का रहा। कंपनी जनवरी-दिसंबर को लेखा वर्ष मानती है।

ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हॉर्लिक्स व बूस्ट ब्रांड अब एचयूएल के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएंगे और यह नेस्ले के माइलो से मुकाबला करेगा, जिसे पिछले साल अगस्त में भारत में दोबारा पेश किया गया था। विश्लेषकों ने कहा कि यह फूड ड्रिंक्स में एचयूएल से मिलने वाली संभावित चुनौती और विलय पूरा होने से पहले नेस्ले की तरफ से तैयारी की जरूरत बताता है। नेस्ले इंडिया के अधिकारी इस मसले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु ऐसा बाजार है जहां माइलो को स्टोर व घरों में आक्रामकता से पेश किया गया है। तमिलनाडु ऐसा बाजार है जहां हॉर्लिक्स काफी मजबूत है क्योंकि इस बाजार में हेल्थ फूड ड्रिंक का उपभोग काफी ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त नेस्ले देश भर में माइलो का ट्रेटा पैक भी उतार रही है ताकि विलय पूरा होने के बाद एचयूएल की तरफ से हॉर्लिक्स के दोबारा पेश किए जाने से पहले लॉयल कस्टमर का आधार बनाया जा सके। अभी जैसी स्थिति है उसके मुताबिक जीएसके कंज्यूमर की हिस्सेदारी हेल्थ फूड ड्रिंक्स में करीब 54 फीसदी है। इनमें हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा और विवा जैसे ब्रांड शामिल हैं। मोंडलीज की बॉर्नवीटा की हिस्सेदारी 15 फीसदी है, वहीं ऐबट की पीडियाश्योर और एन्श्योर की हिस्सेदारी 9 फीसदी है। यह जानकारी उद्योग के आंकड़ों से मिली। नेस्ले अभी तीन अग्रणी कंपनियों में शामिल नहीं है।

लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य में स्थिति बदल सकती है क्योंकि नेस्ले इस श्रेणी में अपनी हिस्सेदारी में सुधार लाने की कोशिश में जुट गई है।

एडलवाइस के कार्यकारी उपाध्यक्ष (शोध - संस्थागत इक्विटीज) अवनीश रॉय ने कहा, हेल्थ फूड ड्रिंक्स के अलावा एचयूएल व नेस्ले और श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेगी। इनमें बेवरिजेज शामिल है जहां नेस्ले की नेस्कैफे और एचयूएल की ब्रू है। इसके अलावा पैकेज्ड फूड बी है जहां एचयूएल के नॉर व किसान ब्रांड हैं जबकि नेस्ले की मैगी है। इंस्टेंट नूडल्स में नेस्ले की हिस्सेदारी पहले ही 60 फीसदी के पार निकल गई है। साथ ही पास्ता, मसाले, केचअप और सूप में भी इसका अच्छा खासा दखल है।

एफएमसीजी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा

- एनसीएलटी की मंजूरी से विलय की रिकॉर्ड तारीख और शेयर आवंटन की घोषणा समेत विलय प्रक्रिया की अंतिम बाधा दूर हो गई
- जीएसके कंज्यूमर के शेयरधारकों को उनके हर शेयर के बदले एचयूएल के 4.39 शेयर मिलेंगे
- जीएसके के एचयूएल में विलय से एचयूएल को नेस्ले के साथ राजस्व का अंतर घटाने में मदद मिलेगी
- जीएसके कंज्यूमर की हिस्सेदारी हेल्थ फूड ड्रिंक्स में करीब 54 फीसदी है। इनमें हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा और विवा जैसे ब्रांड शामिल हैं
- हॉर्लिक्स व बूस्ट ब्रांड अब एचयूएल के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएंगे और यह नेस्ले के माइलो से मुकाबला करेगा, जिसे पिछले साल अगस्त में भारत में दोबारा पेश किया गया था

एयरएशिया इंडिया को 123 करोड़ रुपये का नुकसान

सस्ती विमानन सेवा देने वाली एयरएशिया इंडिया को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 123.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वर्ष 2018 की इसी अवधि में कंपनी का नुकसान 166.15 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी जनवरी-दिसंबर को अपना वित्त वर्ष मानती है। एयर एशिया इंडिया, टाटा समूह और मलेशिया की विमानन कंपनी एयर एशिया की निवेश इकाई एयर एशिया इंवेस्टमेंट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी के बयान के मुताबिक समीक्षावधि में कंपनी की कुल आय 65 फीसदी बढ़कर 1,057.55 करोड़ रुपये रही। 2018 की इसी अवधि में यह 641.17 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी को 597 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो 2018 में 633.61 करोड़ रुपये था। समीक्षा तिमाही में कंपनी की उड़ानों में उपलब्ध सीटों के मुकाबले सीटें भरने की स्थिति भी सुधरी हैं। अक्टूबर-दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी की उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 26.85 लाख रही। *भाषा*

उत्पादन क्षमता में इजाफे की यूनिबिक की योजना

कुकीज बनाने वाली कंपनी की योजना दूसरा प्लांट लगाने की है, 2020 में नई पेशकश भी करेगी

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 1 मार्च

सुस्त मांग के कारण एक ओर जहां नए उत्पादों की पेशकश के मामले में ज्यादातर बड़ी एफएमसीजी कंपनियों की रफ्तार धीमी है, वहीं कुकीज बनाने वाली यूनिबिक ने आक्रामक विस्तार की योजना बनाई है।

35,000 करोड़ रुपये के बिस्कुट बाजार में अपेक्षाकृत छोटी कंपनी (राजस्व करीब 500 करोड़ रुपये) नया संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है, जो उसे अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी करने में मदद करेगा।

कंपनी की योजना मध्य भारत में करीब 87 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र लगाने की है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी श्रीनिवासलु वुदयगिरि ने कहा, नया संयंत्र अगले 14-18 महीने में परिचालन में आ जाएगा और उसकी क्षमता रोजाना 100 टन कुकीज बनाने की होगी। इसके अतिरिक्त वहां स्नेक बार्स व क्रैकर्स के लिए भी प्रॉडक्शन लाइन होगा।

कंपनी का संयंत्र अभी बेंगलूरु के पास तुमकुर में है और वहां सालाना 36,000 टन उत्पादन की क्षमता है। ब्रिटेनिया जैसी बड़ी प्रतिस्पर्धियों के उलट यूनिबिक का ध्यान मोटे तौर पर शहरी बाजार पर रहा है, जो एफएमसीजी क्षेत्र में मांग में सुस्ती से महफूज रहा है।

सीईओ के मुताबिक, कंपनी 15 फीसदी की स्थायी बढ़ोतरी देख र ही है, जो उद्योग के औसत से तीन गुना ज्यादा है। यूनिबिक ने अपना राजस्व दोगुना यानी 1,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि कंपनी की योजना नई श्रेणियों मसलन क्रैकर्स में उतरने और नए उत्पाद पेश करने की है। मौजूदा वित्त वर्ष में यूनिबिक की योजना कुकीज के चार नए वैरियंट पेश करने की है।

हरीश बिजूर कंसल्ट्स के संस्थापक हरीश बिजूर ने कहा, यूनिबिक उच्च श्रेणी वाली बिस्कुट कंपनी है।

एफएमसीजी मांग में सुधार की रफ्तार सुस्त

विशेषज्ञों के अनुसार, खानपान एवं आभूषण जैसे विवेकाधीन कारोबार की मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में लगातार बेहतर रही है जहां खपत में गिरावट आई है

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 1 मार्च

रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाली देश की कुछ शीर्ष कंपनियों का कहना है कि उनके उत्पादों के लिए मांग में सुधार की रफ्तार सुस्त रहेगी क्योंकि बाजार की धारणा अभी भी कमजोर बनी हुई है। लेकिन इस संबंध में विवेकाधीन उत्पादों के कारोबार प्रमुखों के बयानों में अंतर दिख रहा है। टाइटन, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और जुबिलैंट फूडवर्क्स जैसी कंपनियां भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और उनका कहना है कि दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में बिक्री में तेजी दिख रही है।

टाइटन के आभूषण कारोबार के मुख्य कार्याधिकारी अजय चावला ने निवेशकों से बातचीत में कहा, 'चौथी तिमाही (वित्त वर्ष 2020 की) के लिए परिदृश्य लगातार अच्छा दिख रहा है। चौथी तिमाही में हमें बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार पर्याप्त अवसर दिख रहे हैं। हम अपने अनुमानों पर कायम हैं। मार्च तिमाही के लिए हम 11 से 13 फीसदी की वृद्धि (राजस्व में) की उम्मीद कर रहे हैं।'

टाइटन के कुल राजस्व में उसके आभूषण कारोबार का योगदान करीब 80 फीसदी है। तीसरी तिमाही में कंपनी ने आभूषण श्रेणी की बिक्री में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 11 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जिसे मुख्य तौर पर त्योहारी मांग से बल मिला। चौथी तिमाही शादी-विवाह का सीजन है जिससे वृद्धि को रफ्तार मिलने की उम्मीद है जबकि कैलेंडर वर्ष 2020 में सोने की कीमत अब तक 9 फीसदी बढ़ चुकी है।

देश की शीर्ष सूचीबद्ध फूड सर्विस ऑपरेटर वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और जुबिलैंड फूडवर्क्स ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान डाइन-इन बिक्री के मुकाबले डिलिवरी बिक्री अच्छी रही है। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में खाने का ऑर्डर देने का चलन दमदार रहने के आसार हैं। तीसरी तिमाही के दौरान इन दोनों कंपनियों की सेम-स्टोर सेल्स दमदार रही थी और चौथी तिमाही में भी यह प्रवृत्ति बरकरार रहने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों के अनुसार, खानपान एवं आभूषण जैसे विवेकाधीन कारोबार की मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में लगातार बेहतर रही है जहां खपत में गिरावट आई है। दूसरी ओर, एफएमसीजी कंपनियों का ग्रामीण बाजारों में अधिक निवेश है और उनकी कुल बिक्री में इन क्षेत्रों का योगदान करीब एक तिहाई है। विश्लेषकों का कहना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर जैसी कंपनियों की कुल बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान करीब 40 फीसदी है।

नीलसन के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में एफएमसीजी की वृद्धि एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले घटकर लगभग आधी रह गई लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले वह अब भी अधिक है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी की वृद्धि 70 फीसदी से अधिक घट गई। उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल कुछ समय तक यही स्थिति बरकरार रहेगी।

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही तक मांग में सुधार दिख सकता है। उन्होंने कहा, 'रबी सीजन की कटाई होने के साथ-साथ आगामी मॉनसून सीजन प्रमुख कारक होंगे।' उन्होंने कहा, 'सरकार ने भी कल्याणकारी उपायों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन सब कारणों से अगली कुछ तिमाहियों में ग्रामीण क्षेत्रों का दबाव खत्म होना चाहिए।'

वृद्धि की सुस्त रफ्तार को देखते हुए एफएमसीजी कंपनियां आगे के मुश्किल समय के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मलहोत्रा ने कहा, 'हमारी रणनीति फिलहाल कारोबार को बरकरार रखने और अपने ब्रांड पर निवेश करने की होनी चाहिए। हम बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने वितरण नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं।'

गोदरेज कंज्यूमर के मुख्य कार्याधिकारी (भारत और सार्क क्षेत्र) सुनील कटारिया ने कहा, 'हमारी रणनीति द्विआयामी है। हम मात्रात्मक वृद्धि पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसके साथ-साथ प्रीमियम उत्पादों के जरिये हम मूल्य वृद्धि पर भी ध्यान दे रहे हैं।'

बेहतर भविष्य की आस

- टाइटन, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और जुबिलैंट फूडवर्क्स जैसी कंपनियां भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और उनका कहना है कि दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में बिक्री में तेजी दिख रही है

120 साल में बॉन्डों से ज्यादा रहा इक्विटी का प्रतिफल

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 1 मार्च

क्रेडिट सुइस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ईयरबुक 2020 में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के समायोजन के साथ परिसंपत्ति वर्ग के तौर पर इक्विटी ने पिछले 120 साल के दौरान (वर्ष 1900 से) सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है जो बॉन्डों के प्रतिफल की तुलना में 2 प्रतिशत और बिलों के मुकाबले 0.8 प्रतिशत ज्यादा है। ईयरबुक में शामिल देशों ने वर्ष 1900 में वैश्विक इक्विटी बाजार के 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व किया और अभी भी 2020 के शुरू में इनका योगदान 91 प्रतिशत पर बना हुआ है। क्रेडिट सुइस ने इस ईयरबुक के तहत अध्ययन के लिए 23 देशों को शामिल किया। पिछले 120 वर्षों में इक्विटी ने 21 देशों में बॉन्डों, बिलों और मुद्रास्फीति को मात दी। पूरी दुनिया के संदर्भ में, इक्विटी ने प्रतिफल के संदर्भ में बिलों को 4.3 प्रतिशत सालाना और बॉन्डों को 3.1 प्रतिशत तक पीछे छोड़ा।

क्रेडिट सुइस का कहना है कि हालांकि पिछले दशक के दौरान, वैश्विक इक्विटी ने 7.6 प्रतिशत के सालाना वास्तविक प्रतिफल के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि बॉन्डों के लिए यह आंकड़ा 3.6 प्रतिशत रहा। क्रेडिट सुइस के अध्ययन में कहा गया है कि जहां तक बॉन्डों का सवाल है, तो स्वीडन वास्तविक बॉन्ड प्रतिफल के संदर्भ में 1900 से 2.7 प्रतिशत के सालाना प्रतिफल के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन वाला देश रहा है, जिसके बाद 2.4 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत के सालाना प्रतिफल के साथ स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड और कनाडा का स्थान है।

क्रेडिट सुइस में ग्लोबल थीमेटिक रिसर्च के प्रमुख रिचर्ड कसर्ली ने इंटरनैशनल वेल्थ मैनेजमेंट के लिए मुख्य निवेश अधिकारी नानाटे हेचलर-फयदहर्बे द्वारा मिलकर तैयार की गई ईयरबुक 2020 में लिखा है, 'वर्ष 2019 इक्विटी के लिए शानदार वर्ष रहा और ईयरबुक वर्ल्ड इंडेक्स 28 प्रतिशत पर रहा। श्रेष्ठ प्रदर्शन वाला बाजार 56 प्रतिशत प्रतिफल (डॉलर के संदर्भ में) के साथ रूस रहा, जिसके बाद 33 प्रतिशत के साथ स्विटजरलैंड का स्थान रहा। अमेरिकी इक्विटी बाजार ने 30 प्रतिशत का प्रतिफल दिया। वर्ष के शुरू में प्रतिफल की धीमी शुरुआत के बावजूद बॉन्डों ने भी 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया और अमेरिका में इनका प्रतिफल 12 प्रतिशत, ब्रिटेन और स्विटजरलैंड में 9 प्रतिशत और वर्ल्ड इंडेक्स पर 10 प्रतिशत (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) पर रहा।'

क्षेत्रों के संदर्भ में बात की जाए तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार ने वर्ष 1900 से 6.8 प्रतिशत का सालाना प्रतिफल दिया है जिससे यह दुनिया का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बाजार बन गया।

स्वविकसित 5जी के परीक्षण की अनुमति जियो ने मांगी

पृष्ठ-1 का शेष

रिलायंस जियो की प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 5जी परीक्षण के लिए दुनिया की तीन दिग्गज कपंनियों ने एरिक्सन, नोकिया और हुआवे के साथ हाथ मिलाया है। कुछ कंपनियां जेडटीई से भी करार कर रही हैं। जियो के उलट उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां तीन से चार वेंडरों के जरिये अपने 2जी, 3जी और 4जी नेटवर्क का परिचालन कर रही हैं।हालांकि सरकार दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और विनिर्माण में स्थानीय स्तर पर क्षमता विकसित करने पर जोर दे रही है। 2018 में ट्राई स्थानीय दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिए थे।

दूरसंचार नियामक ने घरेलू उत्पादों को तीन श्रेणियों में बांटने और कंपनियों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी।इन श्रेणियों में भारत में डिजाइन लेकिन विदेश में विनिर्माण, भारत में ही डिजाइन और विनिर्माण तथा विदेश में डिजाइन और भारत में निर्माण शामिल है। एरिक्सन जैसी कंपनियां देश में संयंत्र स्थापित करके विनिर्माण कर रही हैं। इस तरह वे विदेश में डिजाइन और स्वदेश में निर्माण कर रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रिलायंस जियो के प्रयास पहली दो श्रेणियों के तहत आ सकता है।इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय दूरसंचार मानक संस्था टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया 5जी परीक्षणों में वैश्विक मानकों के बजाय भारतीय मानकों पर जोर दे रही है। इस संस्था में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उसका कहना है कि वह वैश्विक 5जी मानकों में कुछ बदलाव और विस्तार करेगी ताकि वह भारतीय जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन पुरानी दूरसंचार कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे कई तरह की समस्याएं होंगी।

सोने में गिरावट की आहट

कोरोनावायरस की वजह से लघु अवधि के दौरान बहुमूल्य धातुओं में गिरावट जारी रहने की आशंका, सोने के दामों में आ सकती है 2 से 3 प्रतिशत की कमी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 1 मार्च

निकट अवधि में दो से तीन प्रतिशत की संभावित गिरावट के साथ सोने के दामों पर दबाव बने रहने के आसार हैं। कोरोनावायरस फैलने के कारण वैश्विक बाजार में बिकवाली के बीच निवेशक इक्विटी, धातु, ऊर्जा और मुद्रा जैसे अन्य परिसंपत्ति वर्गों में सुरक्षित मार्जिन पर विचार कर रहे हैं।

अधिकांश वैश्विक बाजारों को वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के बाद से सबसे खराब सप्ताह का सामना करना पड़ा है। सेंसेक्स ने सात प्रतिशत नुकसान के साथ सप्ताह का समापन किया है जिसमें लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का निवेशक धन स्वाह हो गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 1,448 अंक या 3.6 प्रतिशत लुढ़क गया। इसने सोने और चांदी के निवेशकों को अन्य परिसंपत्ति वर्गों में नुकसान पूरा करने के वास्ते बिक्री के लिए प्रेरित किया है।

सराफा

- अगले हफ्ते सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 1,000 रुपये तक गिरकर 40,400 रुपये होने के आसार
- अप्रैल में डिलिवरी वाला सोने का वायदा शुक्रवार को 41,300 रुपये पर बंद हुआ
- चांदी को हुआ और ज्यादा नुकसान
- मई डिलिवरी का वायदा 5.65 फीसदी प्रतिशत गिरकर 44,066 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष नवनीत दमानी का पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,000 रुपये तक गिरकर 40,400 रुपये रह जाएगा।

अप्रैल में डिलिवरी वाला सोने का वायदा भाव शुक्रवार को प्रति 10 ग्राम 41,300 रुपये पर बंद हुआ। इसमें पिछले दिन के मुकाबले 2.56 प्रतिशत की गिरावट आई। चांदी को और ज्यादा नुकसान हुआ। मई में डिलिवरी वाला इसका वायदा भाव 5.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ प्रति किलोग्राम 44,066 रुपये पर बंद हुआ। इन दोनों मूल्यवान धातुओं ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की गिरावट का अनुसरण किया।

वैश्विक संकेतों के बाद शनिवार को मुंबई के हाजिर बाजार सोने के दामों में गिरावट जारी रही। बेंचमार्क जवेरी बाजार में स्टैंडर्ड सोना शुक्रवार को 0.2 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 42,354 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। जनवरी में चीन में कोरोनावायरस का प्रकोप सामने आने के बाद से सोने के दामों 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आने के बाद यह गिरावट आई। शनिवार को सोने का भाव 41,450 रुपये था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें दो प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई।

दामों में काफी अधिक अस्थिरता के बीच उपभोक्ताओं द्वारा नई खरीद से दूरी बनाने के कारण आभूषणों के खुदरा विक्रेताओं नए ऑर्डर का इंतजार है। जवेरी बाजार में सराफा कारोबारी और खुदरा आभूषण विक्रेता उम्मेदमल तिलोकचंद जवेरी के निदेशक कुमार जैन ने कहा कि उपभोक्ता ताजा खरीद के लिए हालात का विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सोने के दामों में और गिरावट आएगी।

बोनांजा पोर्टफोलियो के अनुसंधान प्रमुख विशाल वाघ ने कहा कि सोमवार को सोना गिरावट के साथ खुलने की संभावना है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में नरमी की वजह से भारत में इसका असर अन्य बाजारों की तुलना में कम रहेगा।

हालांकि सोने के लिए दीर्घकालिक परिदृश्य मजबूत बना रहेगा क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी ने सराफा के प्रति सुरक्षित निवेश का आकर्षण बढ़ा दिया है। चीन और जापान जैसे देश पहले ही अपने आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा कर चुके हैं। इससे दुनिया भर में ब्याज दरों में कमी के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। भारत भी आर्थिक प्रोत्साहन के लिए घोषणा की योजना बना रहा है।

वाघ ने कहा कि अगले सप्ताह सोने के दाम प्रति औंस 1,525 से 1,540 के बीच रह सकते है। एक बार कोरोनावायरस नियंत्रण में आ जाए, तो सोने की मांग में फिर से तेजी आएगी। मध्य अवधि में इसके दाम दोबारा प्रति औंस 1,680 डॉलर तक पहुंचकर 1,730 डॉलर के स्तर को पार कर जाएंगे। रुपये के हिसाब से मध्य अवधि में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 44,000 रुपये तक पहुंचने से पहले फिसलकर 40,400 रुपये तक आ सकते हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व वायरस के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जल्द ही अगले महीने तक ब्याज दरों में कटौती करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि आम तौर चांदी सोने का अनुसरण करती है और मजबूत परिदृश्य के कारण इसके दाम सुधरकर 46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंचने से पहले अगले सप्ताह घटकर 42,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ सकते हैं

...रेशम पर भी कोरोना की

सिद्धार्थ कलहंस
लखनऊ, 1 मार्च

चीन से शुरू होकर यूरोप तक फैल चुके कोरोनावायरस के कारण अब उत्तर प्रदेश के रेशम कारोबारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश दुनिया में अपने बेहतरीन रेशमी कपड़ों के लिए मशहूर बनारस में चीन से रेशम के धागों की सप्लाई बीते एक महीने से बंद है। कढ़ाई का काम करने वाले कारीगरों को भी चीन से आने वाले मोती, बीड और अन्य सामग्री नहीं मिल पा रहे हैं।

बनारस के सिल्क कारोबारियों के मुताबिक चीन से आयात बंद होने के बाद रेशम के धागों की कीमत 25 फीसदी बढ़ गई है, जबकि कढ़ाई के काम आने वाले सामान की कीमत 50 फीसदी तक बढ़ गई है। बनारस ही नहीं, देश के अन्य भागों में रेशम के कारीगरों की पहली पसंद मलबरी फ्लैचर धागे हैं जिसकी सबसे ज्यादा खपत होती है। एक महीने पहले तक 3,600 रुपये किलोग्राम बिकने वाला मलबरी फ्लैचर अब 4,400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बिक रहा है। इसके बाद कारीगरों व कारोबारियों की दूसरी पसंद – चायना ड्यूपियान की कीमत भी 2,800 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,400 रुपये पहुंच गई है।

बनारसी रेशम के निर्यातक रजत मोहन पाठक का कहना है कि क्रेप, जॉर्जेट जैसे धागों की कीमत जरूर स्थिर है, लेकिन उसकी मांग भी ज्यादा नहीं है। उनका कहना है कि चीनी रेशम के धागों की कीमत में इजाफा होने के कारण देशी बाजार में तैयार रेशमी कपड़ों व साड़ियों के दाम बढ़े हैं। बाहर जाने वा माल की लागत भी बढ़ गई पाठक का कहना है कि आपूर्ति कब बहाल होगी

पाना मुश्कि चीनी रे फरव हा

आपूर्ति में कमी

- चीन से रेशम के धागों, मोती, बीड आदि की आपूर्ति बाधित
- रेशम के धागों की कीम 25 फीसदी तक बढ़ी
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में के कारोबारियों मुश्किल

हथकरघ किया आ

कृषि निर्यात

अदिति दिवेकर
मुंबई, 1 मार्च

वैश्विक एकीकृत लॉजिस्टिक कंपनी मर्स्क ने जनवरी में नौ दि के भीतर वाराणसी से संयुक्त अमीरात (यूएई) के जेबल बंदरगाह को हरी मिर्च पहली खेप (एंड टू एंड यह कंपनी की सेवा कृषि निर्यात के शुरुआती प्रया

मर्स्क जरिये व्याप कृ

में 60 कर

अमेरिका को शहद निर्यात में अनिवार्य हुई एनएमआर जांच

वाणिज्य मंत्रालय की एजेंसी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ने अमेरिका को निर्यात होने वाले शहद की शुद्धता जांच अनिवार्य रूप से न्यूक्लियर मैगनेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआर) प्रणाली से करने का निर्णय किया है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अमेरिका को निर्यात होने वाले शहद के लिए एनएमआर जांच को 1 अगस्त से अनिवार्य करने के लिए निर्यातकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उम्मीद है कि इस फैसले से देश के ईमानदार शहद उत्पादकों और मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को फायदा होगा। सूत्रों ने कहा कि इस जांच के जरिये अमेरिका को निर्यात होने वाले शहद में किसी भी मिलावट, शहद उत्पादन की जगह और फूल आदि के बारे में अहम सूचनाएं जुटाई जा सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि मिलावटी शहद की शिकायत पर अमेरिका में एक खेमा भारत, यूक्रेन, वियतनाम जैसे देशों के शहद पर डंपिंग रोधी शुल्क लगवाने की कोशिश में लगा है। मिलावटी शहद की आपूर्ति होने के कारण अमेरिका ने चीन के शहद पर 220 प्रतिशत का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया रखा है। पिछले वर्ष भारत को शहद के लिए 1,500 डॉलर प्रति टन का भाव मिला था लेकिन एनएमआर जांच वाले शहद के लिए अब किसानों को 2,000 डॉलर तक का भाव मिलने की संभावना है। *भाषा*

कच्चा इस्पात उत्पादन तीन प्रतिशत घटा

भाषा
नई दिल्ली, 1 मार्च

देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन जनवरी, 2020 में 3.26 प्रतिशत घटकर 92.88 लाख टन रह गया। विश्व इस्पात संघ (वर्ल्ड स्टील) ने यह जानकारी दी है। पिछले साल समान महीने में देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन 95.91 लाख टन रहा था।

वर्ल्ड स्टील की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसे सूचना देने वाले 64 देशों का समीक्षाधीन महीने में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.1 प्रतिशत बढ़कर 15.44 करोड़ टन पर पहुंच गया। जनवरी में चीन का कच्चे इस्पात का उत्पादन 8.43 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले के समान महीने की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक है।

जनवरी, 2020 में जापान का कच्चे इस्पात का उत्पादन 82 लाख टन रहा, जो जनवरी, 2019 की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है। इसी तरह दक्षिण कोरिया का कच्चे इस्पात का उत्पादन 58 लाख टन रहा, जो एक साल पहले के समान महीने से आठ प्रतिशत कम है। दुनिया के इस्पात उत्पादन में वर्ल्ड स्टील के सदस्यों का करीब 85 प्रतिशत का हिस्सा है।

'विवाद से विश्वास' बढ़ाएगी करदाताओं का उत्पीड़न

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 1 मार्च

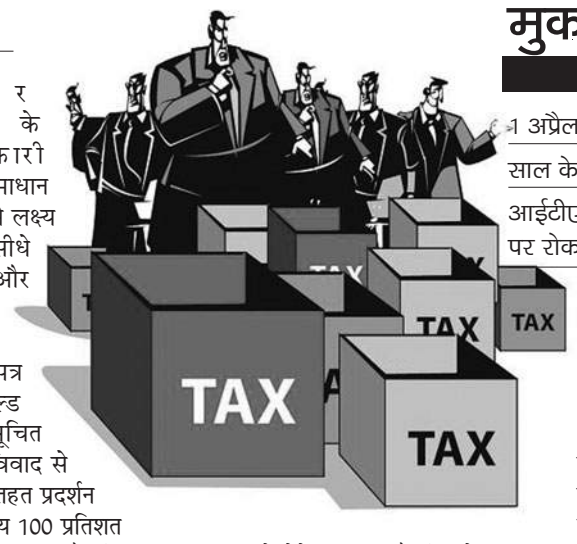

मुकदमेबाजी का प्रबंधन

	वित्त वर्ष 17-18	वित्त वर्ष 18-19
1 अप्रैल तक सीआईटी(अपील) में लंबित मामले	3,28,173	3,21,020
साल के आखिर तक अपील में लगी मांग (करोड़ रु.)	6.39 लाख	5.71 लाख
आईटीएटी/न्यायालयों द्वारा साल के अंत तक मांग पर रोक (करोड़ रु.)	87,035	1,15,837

स्रोतः सीबीडीटी सेंट्रल ऐक्शन प्लान 2019-20

आयकर विभाग के अधिकारी प्रस्तावित विवाद समाधान योजना के अजीब से लक्ष्य से हतप्रभ हैं, जो सीधे उनके पदोन्नति और वेतन वृद्धि से जुड़ा होगा। एक आधिकारिक पत्र व्यवहार में फील्ड ऑफिसरों को सूचित किया गया है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रदर्शन के आकलन का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि कर अधिकारियों को प्रस्तावित योजना के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पात्र मामलों को लेना होगा, जिससे करदाताओं का उत्पीड़न बढ़ने का डर है।

इस समय करदाता पहले ही लगातार फोन कॉल और कर अधिकारियों के दबाव से जूझ रहे हैं और उनके ऊपर योजना के तहत विवाद सुलझा लेने और दर्ज मुकदमे वापस ले लेने का दबाव है। पिछले सप्ताह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से भेजी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 'विवाद से विश्वास योजना में संबंधित फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन के आकलन का लक्ष्य विवादित कर के मामले में 100 प्रतिशत रखा गया है। इस योजना के तहत फील्ड अधिकारियों को 100 प्रतिशत मामलों का समाधान करना होगा।'

प्रत्यक्ष कर अधिकारियों का तर्क है कि 100 प्रतिशत मामलों के समाधान का लक्ष्य अनुचित है और इससे करदाताओं का उत्पीड़न बढ़ सकता है। इसके अलावा उनका तर्क है करदाता को योजना में शामिल होने के लिए दबाव देने का मतलब यह हुआ कि करदाताओं से उनके अपील करने के अधिकार को छीना जा रहा है।

एक कर अधिकारी ने कहा, 'पहले चरण में ही 100 प्रतिशत लक्ष्य कैसे रखा जा सकता है? इससे यह संकेत मिलता है कि आप करदाताओं के अपील करने के अधिकार को छीन रहे हैं और विवाद का समाधान कर रहे हैं।'

इस समय करदाताओं को कर अधिकारियों की ओर से आने वाली कॉल से जूझना पड़ रहा है। नई दिल्ली के एक करदाता ने कहा कि सीआईटी (अपील) या आईटीएटी से मामला वापस लेने और योजना के तहत उसका समाधान करने के लिए कर अधिकारियों की ओर से उनके पास कम से कम 5 बार कॉल आ चुकी है। ऐसा न करने पर उन्हें कर अधिकारियों के पास जाकर सफाई देनी होगी कि वे योजना में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं।

अशोक माहेश्वरी ऐंड एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, 'इन अव्यावहारिक लक्ष्यों का अनपेक्षित असर हो सकता है। सीआईटी (ए) शायद योजना की अवधि तक या तो कोई फैसला नहीं करेंगे या करदाताओं के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। साथ ही हमें नहीं लगता कि इस तरह का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और बड़े करदाताओं के हिसाब से योजना की सफलता सीमित रह सकती है।' एएमआरजी एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, 'कर अधिकारियों को प्रेरित किया गया है कि वे समझाने बुझाने से लेकर बल का इस्तेमाल कर सकते हैं और करदाताओं से योजना में किसी भी हाल में शामिल होने को लेकर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि इसका असर उनके प्रदर्शन, आकलन और मूल्यांकन पर पड़ेगा।' नकदी का प्रबंधन और कंपनी से समय से मंजूरी लेना प्रमुख चुनौती है, जिसका सामना कर आकलन करने वालों को करना पड़ रहा है। घोषणा करने वाले को विवाद से विश्वास फार्म के साथ आयुक्त (अपील), आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से ममला वापस लेने का आवेदन भी लगाना होगा।

संशोधित विवाद से विश्वास विधेयक सोमवार को संसद का सत्र शुरू होने के बाद कभी भी संसद में पेश किया जा सकता है। संसद की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

हकीकत से बहुत दूर है भारत में हरित ऊर्जा का सपना

मिल रही है ताकत

अक्षय ऊर्जा से जुड़ी पारेषण/उत्पादन ऊर्जा गलियारा परियोजनाओं की स्थिति

आवंटित की गई क्षमता गीगावॉट में

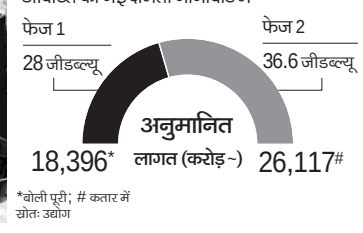

*बोली पूरी; # कतार में
स्रोतः उद्योग

श्रेया जय
नई दिल्ली, 1 मार्च

दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में उच्च सुरक्षा व्यवस्था से घिरी इमारत में स्थित बिजली व्यवस्था ऑपरेटर पीओएसओसीओ से देश की अक्षय ऊर्जा उत्पादन की स्थिति को समझा जा सकता है।

नए केंद्र से 11 अक्षय ऊर्जा प्रबंध केंद्र (आरईएमसी) जुड़े हुए हैं। यह केंद्र सरकार की अक्षय ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के साथ बाधारहित तरीके से जोड़ने की कवायद का हिस्सा हैं, जिससे बिजली ग्रिड में स्थिरता आ सके। उत्तरी क्षेत्र के केंद्र का भवन निर्माणाधीन है, लेकिन मौजूदा पीओएसओसीओ केंद्र के पास स्थित पूरक इकाई ने भारत की आरई की निगरानी शुरू कर दी है।

आरईएमसी में रियल टाइम मौसम भविष्यवाणी की व्यवस्था है, जिसमें बादलों की सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल होता है। इसमें सभी सौर और पवन परियोजनाओं के लोड प्रोफाइल का लाइव अपडेट होता है। इसमें उत्पादन के आंकड़े, अगले दिन उत्पादन का अनुमान, यहां तक कि सप्ताह के उत्पादन और उसके डिस्पैच की योजना होती है। एक आरईएमसी की स्थापना में 15 से 20 करोड़ रुपये लगते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक पहले ही काम कर रहा है।

निश्चित रूप से ये केंद्र प्रभावी दिखते हैं, लेकिन आंकड़े प्रभावित नहीं करते। दिसंबर में देश भर में हुई 98.76 अरब यूनिट बिजली की आपूर्ति में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 9.5 प्रतिशत है। अप्रैल नवंबर 2019 में देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में आरई की हिस्सेदारी महज 8.2 प्रतिशत थी।

पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत भारत ने 2040 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत उत्पादन का लक्ष्य लक्ष्य रखा है। लेकिन इसमें कोयला आधारित बिजली उत्पादन कम करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। भारत के कुल बिजली उत्पादन में ताप बिजली की हिस्सेदारी अभी भी 80 प्रतिशत के करीब है। ग्रिड प्रबंधकों को सबसे पहले इसका सामना करना पड़ता है। पवन ऊर्जा का उत्पादन साल के कुछ महीनों में होता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन 6 से 8 महीने होता है। इसके अलावा यह इकाइयां देश के कुछ ही हिस्सों में केंद्रित हैं। कंपनी के स्तर पर अक्षय ऊर्जा की अनिरंतरता की निगरानी भी की जा सकती है। कंपनी की पयोजनाओं के उत्पादन के ड्रोन से लिए आंकड़े 10 राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं, जिससे बिजली के उत्पादन का अनुमान और उनके शेड्यूलिंग में सहूलियत होती है।

उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नजदीक के स्टेशनों पर बिजली भेजना और अन्य क्षेत्रों में बिजली को भेजना है। इससे निपटने के लिए केंद्र ने हरित ऊर्जा गलियारे (जीईसी) की घोषणा की है, जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित पारेषण नेटवर्क है।

जिस रफ्तार से परियोजनाएं आ रही हैं, उसकी तुलना में परियोजनाओं पर काम की रफ्तार सुस्त है। जीईसी के पहले चरण में करीब 20 जीडब्ल्यू पारेशण क्षमता सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने तैयार की। आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु और राजस्थान में सिर्फ दो परियोजनाएं आने वाली हैं। वहीं 20 जीडब्ल्यू के लिए निजी कंपनियों ने बोली लगाई है। इसके अलावा और 66 जीडब्ल्यू की परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिसमें से 28 जीडब्ल्यू की बोली हो चुकी है।

केंद्र ने मेगा सोलर पार्क स्थापित करने का भी फैसला किया है, जिनकी अपनी पारेषण व्यवस्था होगी। प्रमुख फर्में आंतरिक पारेषण व्यवस्था तैयार करेंगी, जिसकी वजह से पार्क के अंदर के संयंत्रों की बिजली 30 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। कुछ अक्षय ऊर्जा कंपनियां पारेषण में निवेश कर रही हैं। आपूर्ति में सुधार व उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है।

इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि अक्षय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन का विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ राज्य बिजली नियामक आयोगों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए शुल्क तय करने में देरी की वजह से इस क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति है। इसके अलावा कुछ बिजली वितरण कंपनियां भुगतान में देरी कर रही हैं। दिसंबर 2019 में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर वितरण कंपनियों का बकाया 9,000 करोड़ रुपये है।

भारत ने 2022 तक 175 जीडब्ल्यू अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें महज 2 साल बचे हैं। ऐसे में अक्षय ऊर्जा को लेकर संदेह बना हुआ है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में तेज बढ़ोतरी के बावजूद इनमें से ज्यादातर में कुछ साल में रिटर्न मिलना कठिन है। एक तरफ पारेषण नेटवर्क का अभाव है, वहीं राज्य इसके लिए भुगतान करने को भी तैयार नहीं हैं। अब योजनाकारों को हकीकत पर नजर डालनी चाहिए कि अक्षय ऊर्जा ज्यादा है, जबकि पारेषण व्यवस्था कम है, साथ ही इसके लिए मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है।

(नोट: यह खबर स्मितु कोठारी फेलोशिप प्रोग्राम 2019 के सहयोग से प्रकाशित की गई है।)

विदेश जैसा बनेगा मेगा शॉपिंग केंद्र

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 1 मार्च

- **डीडीए पीरागढ़ी में 20 अप्रैल को नीलाम करेगा 11.58 हेक्टयर जमीन**
- **जमीन के लिए आरक्षित मूल्य है करीब 2,958 करोड़ रु**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मेगा शॉपिंग हब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस केंद्र के लिए पीरागढी में एक बड़े एकीकृत व्यावसायिक केंद्र को विकसित करने के लिए जमीन की नीलामी की तैयारी कर ली है। इस केंद्र में शॉपिंग, मनोरंजन, कला व संस्कृति आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही एक होटल के लिए भी जमीन दी जाएगी। इस केंद्र में लोग परिवार के साथ खरीदारी और खान-पान का आनंद ले सकेंगे।

डीडीए के एक अधिकारी बताया कि विदेश में बड़े शॉपिंग केंद्र होते हैं। डीडीए इसी तरह के केंद्र दिल्ली में बनाना चाहता है। इस केंद्र के लिए पीरागढ़ी में करीब 1.15 लाख वर्ग मीटर जमीन की नीलामी के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें 2.29 लाख वर्ग मीटर कवर्ड एरिया और 12,537 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र होगा। इस केंद्र में 375 एफएआर अनुमति के साथ 7,000 वर्ग मीटर होटल के लिए भी जमीन रखी गई है। केंद्र के लिए 20 अप्रैल को जमीन की ई-नीलामी की जाएगी। इच्छुक पक्ष 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस जमीन का आरक्षित मूल्य करीब 2,958 करोड़ रुपये रखा गया है।

पीरागढ़ी में बनने जा रहे इस केंद्र में खरीदारी के लिए दुकानों के साथ बड़े डिस्काउंट स्टोर, फैक्टरी आउटलेट, खाने-पीने की दुकानों के साथ ही लोगों के मनोरंजन और उनके आराम के लिए भी सुविधाएं होंगी। कला व संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी सेवाएं मिलेगी। यह केंद्र उसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है जिस तरह अमेरिका में सप्ताहंत पर लोग परिवार के साथ घूमने और शॉपिंग करने के लिए आते हैं। पीरागढ़ी में विकसित होने वाले इस केंद्र में अमेरिका की तरह नियमित रूप से आने वालों के लिए सदस्यता की सुविधा भी दी जा सकती है। यह केंद्र दो मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट के साथ ही रिंग रोड से जुड़ा है। इस तरह के केंद्र दिल्ली में और भी जगह बनाए जा सकते हैं, जिससे दिल्ली को सही मायने में मेट्रोपोलिटन शहर बनाया जा सके।

'सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे'

भाषा
कोलकाता, 1 मार्च

रविवार को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी के अन्य नेता -पीटीआई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जब तक सीएए के तहत देश में सभी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दे दी जाती तब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं रुकेगी। वहीं शाह के दौरे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियों, कांग्रेस और माकपा ने कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं। उधर भाजपा के कार्यकर्ताओं की गोली मारो... की नारेबाजी कोलकाता में भी जारी रही।

शाह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से अगली सरकार बनाएगी। तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के चलते एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं गंवानी पड़ेगी।

गृहमंत्री ने कहा, 'विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है...मैं अल्पसंख्यक समुदाय के हर व्यक्ति को आश्वस्त करता हूं कि सीएए केवल नागरिकता देता है, न कि छीनता है। इससे आपकी नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा।'

उन्होंने कहा, 'जब तक सभी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं रुकेंगे।' शाह ने रैली में पश्चिम बंगाल में भाजपा की 'अब और अन्याय नहीं' मुहिम का भी शुभारंभ किया।

पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत भारत ने 2040 तक अपने कुल बिजली उत्पादन में से 40 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन से करने की प्रतिबद्धता जताई है

बीएस बातचीत

सूक्ष्म वित्त संस्थानों को जिम्मेदारी से कर्ज देने की जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिबंध हटने के बाद बंधन बैंक एक महीने में 250 शाखाएं खोलने पर विचार कर रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब माइक्रोफाइनैंस उद्योग पर दबाव नजर आ रहा है। बंधन का करीब 60 प्रतिशत कारोबार माइक्रोफाइनैंस में है, उस पर एक साझा आचार संहिता पर हस्ताक्षर का दबाव है। बैंक के कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक **चंद्रशेखर घोष** ने **नम्रता आचार्य** के साथ बातचीत में बताया कि संहिता क्यों सही नहीं है। प्रमुख अंश...

शाखाएं खोलने को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने से वृद्धि पर कैसे असर पड़ेगा?
बोर्ड की मंजूरी के बाद जब हम शाखाएं खोलना चाहते थे तो हमें रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसमें वक्त लगता था। अब समय ज्यादा लगने से वृद्धि प्रभावित नहीं होगी।

नई शाखाओं का लक्ष्य क्या है?
हम मार्च के अंत तक देश में 250 नई शाखाएं खोलेंगे।

प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर रिजर्व बैंक के मानकों को लेकर आपकी क्या योजना है?
हमारे पास अच्छी योजना है। हमारा पहला लक्ष्य अनुपालन है।

खबर है कि सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) बैंक से बाहर निकलना चाहता है। क्या इस पर कोई चर्चा हुई है?
सिडबी की बैंक और होल्डिंग कंपनी (बंधन की) में हिस्सेदारी थी। उन्होंने पहले ही बैंक के स्तर पर बिक्री कर दी है। यह आईपीओ के बाद हुआ। होल्डिंग कंपनी के बारे में उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है।

असम में बड़े पैमाने पर चूक की खबरें हैं। इसका कितना असर है?
इसका हम पर कोई असर नहीं है। वहां हमारी पुनर्भुगतान दर 93 प्रतिशत है। यहां तक कि दिसंबर जैसे बुरे दौर में पुनर्भुगतान 80 प्रतिशत था। कुछ अस्थाई समस्याएं हैं और इससे बैंक के कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा।

लॉबी समूह एमएफआईएन (माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क) सभी कर्जदाताओं के लिए एक सामान्य आचार संहिता पर जोर दे रहा है। क्या आप इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं?
नहीं। संहिता पर हस्ताक्षर के लिए वे हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हम एक सार्वभौम बैंक हैं, इसलिए उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। संहिता में दायित्वपूर्ण उधारी की बात कही गई है। हम ऐसा शुरुआत से ही कर रहे हैं। हमारी ब्याज दरें हमेशा सबसे कम रही हैं। एमएफआई को जिम्मेदारी से कर्ज देने की जरूरत है। हम लक्ष्य के आधार पर कर्ज नहीं देते हैं। हर साल हम 20 प्रतिशत नए ग्राहक जोड़ रहे हैं। संहिता में एमएफआई का कहना है कि तीन कर्जदाताओं में से 2 एमएफआई होने चाहिए। एमएफआई को यह फैसला क्यों करना चाहिए कि कर्ज लेने वाले 3 लोग बैंक में जाएं या 3 लोग एमएफआई में जाएं?

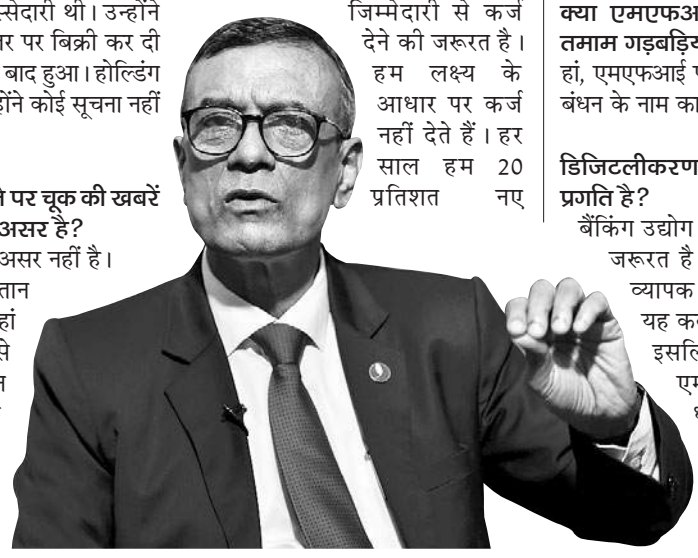

क्या एमएफआई में ओवरलेंडिंग है?
बंधन पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है। एमएफआई उन ग्राहकों को कर्ज देने के लिए चुन रहे हैं, जिन्होंने बंधन से पहले कर्ज लिया है।

क्या एमएफआई के कर्ज देने में तमाम गड़बड़ियां हैं?
हां, एमएफआई पूर्व में कर्ज देने के लिए बंधन के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

डिजिटलीकरण में आपकी क्या प्रगति है?
बैंकिंग उद्योग में डिजिटलीकरण की जरूरत है। माइक्रोक्रेडिट कर्ज व्यापक मॉडल है। बहरहाल यह कब तक चल सकता है? इसलिए अब उन्होंने एमएसएमई की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। सूचना तकनीक आंकड़ों के विश्लेषण में मदद देती है, जिससे जोखिम कम करने के लिए त्वरित फैसले किए जा सकें।

बंधन बैंक में महिलाओं ने कितना एमएसएमई कर्ज लिया है?
अच्छी संख्या है। न सिर्फ महिलाएं आ रही हैं बल्कि उनके पति भी उद्यम को परिवार के कारोबार में तब्दील कर रहे हैं।

आपके कर्ज के पोर्टफोलियो में किस तरह का बदलाव हो रहा है?
अगले 3 साल में हमारा 50 प्रतिशत कर्ज सस्ते आवास और एमएसएमई क्षेत्र में होगा। इस समय गृह की 195 शाखाएं हैं और हमने 106 खोली हैं। इस तरह से आवास ऋण के लिए हमारी 301 समर्पित शाखाएं हैं। पिछले समय में गृह के आवास ऋण का औसत 10 लाख रुपये है। हम अब यह बढ़कर 12 लाख रुपये हो गया है। सस्ते आवास के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं।

क्या राजनीतिक बाधाओं से ग्रामीण कर्ज पर पड़ने वाला असर चिंता का विषय है?
नहीं। सामान्यतया ऐसी स्थिति एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रहती। आज असम में हो स्थिति है, उसकी तुलना में नोटबंदी के समय में स्थिति बहुत खराब थी। हमारे लिए यह समस्या नहीं है।

भारत का सबसे बड़ा सौर विनिर्माण टेंडर अटका

श्रेया जय
नई दिल्ली, 1 मार्च

सौर विनिर्माण के लिए भारत का पहले और सबसे बड़े टेंडर को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) ने अभी ग्रीनशू ऑप्शन के लिए अधिकार पत्र (एलओए) को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिससे कंपनियों को अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की अनुमति मिलती है।

देरी और 2 साल के करीब समय बढ़ाए जाने के बाद सौर विनिर्माण के लिए नवंबर 2019 में बोली मिली थी। सरकार ने 2,000 मेगावॉट सौर विनिर्माण और उससे जुड़े 6,000 मेगावॉट सौर बिजली संयंत्र के लिए बोली आमंत्रित की थी। इसे उद्योग की ओर से अतिरिक्त अभिदान मिला था।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 1,000 मेगावॉट के विनिर्माण और 4,000 मेगावॉट के बिजली संयंत्र के लिए बोली दाखिल की। अजूरे पॉवर ने 500 मेगावॉट के विनिर्माण और 2,000 मेगावॉट के बिजली संयंत्र के लिए बोली पेश की। सूत्रोंने कहा कि अदाणी और अजूरे दोनों ने ही 2.9 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर की पेशकश की थी।

इसमें बोली लगाने वालों के लिए ग्रीनशू का विकल्प था, जिसे वे विनिर्माण व बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते थे। इस विकल्प के तहत अदाणी ने 1,500 मेगावॉट सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण और 6,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की अतिरिक्त पेशकश की थी। अजूरे ने 500 मेगावॉट विनिर्माण व 2,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की पेशकश की थी।

एजर पावर ने दिसंबर में घोषणा की कि उसे प्राथमिक रूप से 2 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमका के लिए एलओए मिला है। अदाणी ने अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। वहीं सूत्रों ने कहा कि एसईसीआई के बोर्ड ने बोली के ग्रीनशू वाले हिस्से के एलओए को मंजूरी नहीं दी है। बोली की प्रक्रिया की गोपनीयता का हवाला देते हुए एसईसीआई के प्रबंध निदेशक जेएन स्वैन ने कहा कि जल्द ही बोली आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम कुछ स्पष्टीकरण ले रहे हैं। हमने बिजली उत्पादन, विनिर्माण वाले हिस्से के लिए पहले ही एलओए दे दिया है और ग्रीनशू वाले हिस्से पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा।'

इस क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा कि एसईसीआई बोर्ड ग्रीनशू ऑफर को मंजूरी देने के लिए फैसला करेगा और साथ ही इसे दो विजेताओं को आवंटित करेगा। विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देने में ऐसे समय में देरी हो रही है, जब सौर पैनलों का आयात सरकार के संरक्षणवादी कदमों के कारण तेजी से गिरा है। घरेलू बाजार को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने आयातित सौर सेल, मॉड्यूल व पैनलों पर 2018 में 2 साल के लिए संरक्षण शुल्क लगा दिया था। मौजूदा शुल्क 15 प्रतिशत है और जुलाई में इसकी तिथि खत्म होगी। इस अवधि के दौरान घरेलू विर्माण के ठेकों में भी देरी हुई। इससे सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में देरी हुई क्योंकि डेवलपरों ने आयात रोक दिया और इसका घरेलू उद्योग को कोई फायदा नहीं हुआ।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 13

सुधार प्रक्रिया को जोखिम

अधिकांश विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक ही वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी आर्थिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 4.7 फीसदी की दर से विकसित हुई जबकि पिछली तिमाही में संशोधित अनुमान 5.1 फीसदी था। दूसरी तिमाही की वृद्धि दर के पहले 4.5 फीसदी रहने की बात कही गई थी। वर्ष 2018-19 के लिए और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए भी अनुमानों को संशोधित किया गया और अब यह 5.6 फीसदी की वृद्धि दर दर्शा रहा है। जबकि पहले इसके 5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। हालांकि चालू वर्ष के पूरे वर्ष के अनुमान बरकरार हैं लेकिन विशुद्ध उत्पादन अनुमान में करीब 95,000 करोड़ रुपये की कमी की गई। इससे वृद्धि अनुमान प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि पिछले वर्ष के उत्पादन अनुमान में भी इतना ही संशोधन हुआ। वर्ष 2018-19 की वृद्धि दर को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.1 फीसदी कर दिया गया। इन अहम संशोधनों के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के धीमी गति से विकसित होने की अनुमान है। हालांकि बाद में इसमें पुन: संशोधन हो सकता है।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र 3 फीसदी की दर से विकसित हुआ, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई। चिंता की बात यह है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच निवेश में काफी कमी आई। माना जा रहा है कि पूरे वर्ष के दौरान यह ऋणात्मक दायरे में रहेगा। मौजूदा आर्थिक कमजोरी और अन्य उभरती चुनौतियां यही सुझाती हैं कि अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में कोई खास सुधार नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए वित्तीय सेवा समूह नोमुरा के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि दिसंबर तिमाही की समग्र वृद्धि में विशुद्ध निर्यात और सरकारी व्यय की हिस्सेदारी 2.7 फीसदी रही। कम आयात जहां कमजोर मांग का परिचायक रहा वहीं चालू तिमाही में सरकारी व्यय को भी सीमित रखना होगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजकोषीय घाटा जनवरी में ही पूरे वर्ष के लक्ष्य का 128 फीसदी हो चुका था। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोनावायरस के प्रसार ने भी अनिश्चितता बढ़ाने में भूमिका निभाई है। इस वायरस के प्रसार के केंद्र चीन में आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचने के अलावा यह मांग में कमी की वजह भी बन सकता है। यह गिरावट अनुमान से लंबी चल सकती है। आर्थिक गतिविधियों पर इस बीमारी के असर की आशंका से पिछले सप्ताह वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। औषधि, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत चीन पर निर्भर है। घरेलू उत्पादन को जोखिम के अलावा वैश्विक वृद्धि में धीमापन आर्थिक भविष्य को भी प्रभावित करेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इकलौती सकारात्मक बात जिंस कीमतों में कमी है।

अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में मौद्रिक नीति से कुछ खास मदद मिलने की आशा भी नहीं है। हाल के महीनों में शीर्ष मुद्रास्फीति में इजाफे का कारण बनी खाद्य कीमतों में कमी आ सकती है, अन्य क्षेत्रों से भी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कीमतों पर आपूर्ति श्रृंखला की विसंगतियों का दबाव है, ऐसे में दरें तय करने वाली समिति यह देखना चाहेगी कि दूरसंचार क्षेत्र का घटनाक्रम शुल्क दरों और शीर्ष मुद्रास्फीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक लंबी अवधि की रीपो दर की सीमा बढ़ाना चाहेगा ताकि तरलता बढ़ाई जा सके और बाजार दर कम की जा सके। बहरहाल, कीमतों और नकदी की स्थिति देखते हुए इस विकल्प की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में आज जो हालात हैं उनके मुताबिक आने वाली तिमाहियों में वृद्धि धीमी बनी रह सकती है। लंबी अवधि की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति समेत बुनियादी समस्याओं से कितनी जल्दी निपटती है।

अजय मोहंती

दंगों की मूल वजह पर चर्चा का वक्त

दिल्ली के दंगे हमें याद दिलाते हैं कि कैसे सीएए-एनआरसी का जहर देश के माहौल को विषाक्त बना रहा है। खेद की बात है कि यह देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा बोई गई विषबेल की वजह से हो रहा है।

क्या यह सही वक्त है जब हम एक ऐसी समस्या की जड़ों के बारे में चर्चा करें जबकि देश की राजधानी इसकी वजह से जल रही है? और यह भी कि विभाजन के बाद पहली बार हिंदू-मुस्लिम दंगों में शहर में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो चुकी हैं?

यह देश का सबसे सुरक्षित शहर है। यह सब राष्ट्रपति भवन से 8-10 किलोमीटर के दायरे में हुआ जो हमारे गणतंत्र का गौरव है और जिसके आसपास साउथ और नॉर्थ ब्लॉक स्थित हैं जहां देश के घरेलू और सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कार्यालय हैं जो देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

क्या इस काम को बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, तब तक जब तक कि यह उबाल शांत नहीं हो जाता और सरकार तथा न्यायपालिका समेत विभिन्न प्रतिष्ठान हालात सामान्य नहीं कर लेते? बौद्धिक बहसें प्रतीक्षा कर सकती हैं, तब तक जब तक यह आग और भावनाएं शांत नहीं हो जातीं।

किसी भी तरह के टकराव, जन असंतोष, उपद्रव या आतंकवाद से जुड़ी बहस उस वक्त थम जाती है जब बात उसके पीछे मूल वजह की आती है। बहस में शामिल पक्षकार उसके पक्ष या विपक्ष में अडिग हो जाते हैं और गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद भड़काना और उस पर भारत की प्रतिक्रिया इसका उदाहरण है। इस वक्त असहज करने वाले सवाल पूछने के अलग जोखिम हैं। कोई मंत्री या एक मंत्री अथवा सोशल मीडिया के शूरवीरों की टुकड़ी आप पर मनचाहे ढंग से हमला कर सकती है। आप पर भड़काऊ बातें करने से लेकर राजद्रोह तक के इल्जाम लगा सकती है। अदालत भी आपको नोटिस जारी कर सकती है। यही कारण है कि टेलीविजन चैनलों को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे प्रसारण संहिता का पालन करें। हालांकि तब तक जो नुकसान होना था, हो चुका था। अब हम इतने भयभीत हैं कि हम सरकार से इस बात के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं कि वह सत्ता केंद्र से मात्र छह किमी की दूरी पर हालात नहीं संभाल सकी।

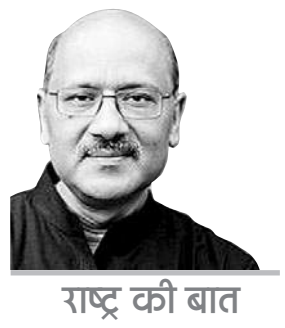

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

हालांकि हम इतने कायर भी नहीं हैं कि एक अन्य संस्था से यह कुतर्क करें कि वह भी उन नागरिकों की रक्षा में नाकाम रही। जबकि यह संस्था पीड़ितों से बमुश्किल 5 किमी की दूरी पर थी। ध्यान रहे यहां मामला, मिलीभगत, अक्षमता या विचारधारा का नहीं है। हम आमतौर पर सरकारों पर यही इल्जाम लगाते हैं।

यहां मामला उस संस्था द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल न करने और अपनी संस्थागत तथा नैतिक पूंजी को गंवाने का है, जो मौजूदा हालात में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। देश की राजधानी में लगी आग जो पूरे देश में सुलग रही है, उसकी वजह उस संस्था में निहित है जिसे इसके कारणों की बेहतर समझ होगी। जाहिर है सबसे प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुष सर्वोच्च न्यायालय चलाने के लिए चुने जाते हैं। जाहिर है वे इन परिणामों से अनभिज्ञ नहीं होंगे।

सीएए-एनआरसी का जो जहर आज देश को विषाक्त कर रहा है, दुख की बात है कि उसकी विष बेल देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस वक्त बोई थी जब न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और रोहिंटन नरीमन के पीठ ने अपनी निगरानी में असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का काम शुरू करने का आदेश दिया। हमें इस बात को रेखांकित करना होगा कि न्यायाधीशों ने अचानक उत्पन्न किसी समझ से यह निर्णय नहीं लिया होगा। असम और वहां आव्रजन के उलझे हुए इतिहास में विदेशी नागरिक का मुद्दा प्रबल है। सन 1980 के दशक में इस मुद्दे पर एक व्यापक लोकप्रिय आंदोलन ने राज्य को पंगु बना दिया था। वहां तीन साल तक सरकार की कुछ नहीं चली थी। उस दौर में असम में उत्पादित कच्चे तेल की एक बूंद बाहर रिफाइनरी तक नहीं पहुंची। स्थानीय असमी लोगों में गुस्सा इस बात का था कि बांग्ला बोलने वाले घुसपैठिये स्थानीय संस्कृति, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर चुके हैं। जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता रहा है, व्यापक शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ उग्रवादी तत्त्व उभर गए। सन 1985 के जाड़ों में हालात तब सामान्य हुए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के प्रावधानों में एक प्रावधान व्यापक एनआरसी, अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनका नाम मतदाता सूची से बाहर करने और अंतत: उन्हें वापस भेजने का भी था।

असम के विशेष संदर्भ में इसकी तारीख तय की गई 25 मार्च, 1971 यानी वह दिन जब पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया था। इसके पीछे विचार यही था कि सन 1947 के बाद से ही दमन से बचने के लिए लाखों हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान से असम में शरण ली। उन्हें भारत में शरण मिलनी चाहिए थी। सरल शब्दों में कहें तो जब तक पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व था, वहां से आने वाले किसी व्यक्ति से कोई सवाल या उस पर कोई संदेह नहीं किया जाना था। 25 मार्च, 1971 के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों की देखरेख की जवाबदेही बांग्लादेश की मित्रतापूर्ण सरकार की थी।

यानी उस तय तारीख के बाद देश में आने वाले लोग अवैध विदेशी थे और उन्हें वापस भेजा जाना था। बांग्लादेश ने उन्हें वापस लेने की हां की थी चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। समझौते में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया था। न्यायाधीश भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें समझौते के इस अहम प्रावधान को लागू करने की बात कही गई थी और जिसे सभी भुला बैठे थे।

आप कानूनी दृष्टि से यह पूछ सकते हैं कि न्यायाधीशों ने भुला दिए गए असुविधाजनक तथ्य की अनदेखी केवल इसलिए की क्योंकि वह राजनीतिक और व्यावहारिक दृष्टि से सुविधाजनक था?

बाकी बातें हाल की हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पीठ की निगरानी में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई।

न्यायालय ने एनआरसी के प्रभारी को अपने अधीन रखा और कहा कि वह मीडिया समेत किसी से बात नहीं कर सकता। इससे पूरी प्रक्रिया को लेकर अस्पष्टता और भय का माहौल बना। अदालत ने यह आदेश भी दिया कि अवैध विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। परंतु जब हकीकत सामने आई तो सबकुछ बदल गया। कुछ लोग सामने आए तथ्यों से नाराज थे लेकिन ताकतवर लोगों को इसमें अवसर नजर आया।

जो विदेशी चिह्नित किए गए वे पहले की गई कल्पना की तुलना में नाम मात्र थे। अवैध साबित लोगों में से दो तिहाई बंगाली हिंदू निकले। स्थानीय असमी न तो हिंदुओं को स्वीकार करेंगे और नही सन 1985 के समझौते की दलील अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके क्रियान्वयन को। क्या भाजपा हिंदुओं को निकाल सकती है?

अब हम कहां हैं? भाजपा को इसमें अवसर नजर आया। असम के हिंदू घुसपैठियों को नए सीएए की मदद से सुरक्षित किया जा सकता है और यह मुस्लिमों से निपटने के काम आएगा। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे एक राज्य के लिए वैध कर दिया है और डिटेंशन सेंटर की राह तक सुझा दी है तो इसे पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? यह ध्रुवीकरण का ऐसा मंत्र बन गया जो सबको जीत सकता है।

अब हम यहां पहुंच गए हैं। सीएए की संवैधानिकता की नई गेंद उसी पाले में उछल रही है। इस बीच भली मंशा से बोया गया जहर पूरे देश में फैल रहा है। असम में भी अब भाजपा की सरकार कह रही है कि वह एनआरसी से नाखुश है और इसे दोबारा अंजाम देना चाहती है। जिस अधिकारी ने अदालत की निगरानी और संरक्षण में इसे अंजाम दिया, उसे परेशान किया जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वह सही आंकड़े नहीं जुटा सके। अब तक सर्वोच्च न्यायालय को भी उसका बचाव करते नहीं देख पाए हैं जो उसकी निगरानी में हुआ। उसने यह भी नहीं कहा कि वह दोबारा एनआरसी की प्रक्रिया नहीं होने देगा या अपने इरादों को सीएए के माध्यम से समाप्त नहीं होने देगा। दिल्ली का दंगा तो एक घटना है। इसमें बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश को जोड़ लीजिए तो मृतकों की तादाद बहुत बड़ी नजर आएगी। दुख की बात है कि यह एक लंबे अंधकारमय दौर की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अब इसकी जड़ों पर विचार करने का समय आ गया है।

परमाणुओं की अंत:क्रिया संबंधी नए प्रयोग से जगी उम्मीद

तकनीकी तंत्र
देवांशु दत्ता

न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी के एक शोध दल ने एक असाधारण प्रयोग करते हुए आणविक संयोजन की प्रक्रिया में तीन अलग-अलग परमाणुओं की अंत:क्रिया के पृथक्करण एवं निरीक्षण में कामयाबी हासिल की है। यह रासायनिक गतिविधि एक विशेष कैमरे पर रिकॉर्ड की गई थी और इससे आणविक प्रक्रियाओं के बारे में अप्रत्याशित विवरण सामने आते हैं।

शीत परमाणु त्रिमूर्ति में संघटनकारी गतिशीलता के प्रत्यक्ष मापन के तौर पर परिभाषित इस प्रयोग में रुबिडियम के तीन परमाणुओं को फंसाकर उन्हें परम शून्य तापमान तक ठंडा किया गया। रुबिडियम के अणु में दो परमाणु होते हैं लेकिन आणविक संयोजन की रासायनिक प्रक्रिया के लिए कम-से-कम तीन परमाणुओं की जरूरत होती है। जब एक अणु बनता है तो सभी तीनों परमाणुओं में 'ऊर्जा का प्रस्फुटन' होता है जिसे त्रिपिंडीय पुनर्संयोजन कहा जाता है।

इस प्रयोग के पहले वैज्ञानिक आणविक गठन की प्रक्रिया समझने के लिए अक्सर परमाणुओं के विशाल 'बादलों' की अंत:क्रिया का मॉडल अपनाते रहे हैं। लिहाजा इस प्रक्रिया का सांख्यिकीय संदर्भों में अध्ययन किया गया है और कई परमाणुओं की अंत:क्रिया के आंकड़े भी हैं। लेकिन न्यूनतम तीन परमाणुओं की अंत:क्रिया के इस अध्ययन में नई जानकारियां सामने आईं।

एक टोस्टर के आकार वाले एक निर्वात चैंबर के भीतर तीन शीत परमाणुओं पर लेजर किरणें डाली गईं। अत्यधिक केंद्रित लेजर प्रकाश-पुंज का उपयोग सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को गिरफ्त में लेने और उनके दोहन के लिए होता है।

लेजर किरणें डालने से एक क्षेत्र बनता है जिसमें लक्षित कण भी मौजूद होता है। लेजर की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होती है उतने ही छोटे वस्तु का इस्तेमाल परमाणु को पकड़ में लेने के लिए किया जा सकता है। ऑप्टिकल ट्वीजर का इस्तेमाल अलग-अलग अणुओं को गिरफ्त में लेने के लिए होता रहा है और जैव-अणुओं के अध्ययन में इनका इस्तेमाल भी आम बात है। उदाहरण के तौर पर ऑप्टिकल ट्वीजर का इस्तेमाल विषाणुओं को चिह्नित करने और उनके अध्ययन में होता रहा है।

छोटे पदार्थों को इंगित करने के लिए लेजर किरणों के इस्तेमाल की इस परिघटना की खोज 1970 के दशक के शुरुआत में आर्थर एशकिन ने की थी। उस समय बेल प्रयोगशाला में कार्यरत एशकिन और उनकी टीम ने 1986 में पहली ऑप्टिकल ट्वीजर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। इन उपलब्धियों के एवज में एशकिन को 2018 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह प्रयोग वह पहला मौका था जब अलग-अलग परमाणुओं को फंसाया गया और कुछ के साथ अंत:क्रिया के लिए बाध्य किया गया। परमाणुओं को परम शून्य के करीब तापमान तक ठंडा कर दिए जाने के बाद तीन अलग फंदों का इस्तेमाल निर्वात चैंबर के भीतर तीनों परमाणुओं को पृथक करने के लिए किया गया। फिर इन तीनों फंजों को एक-दूसरे के इतना करीब लाया गयाा कि ये परमाणु एक-दूसरे से क्रिया कर सकें। दो फंदों को हटा लिए जाने के बाद तीनों परमाणु उस अकेले फंदे में ही टकराते रहे।

इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया और हरेक बार टकराव की गतिशीलता को देखा गया। इसके परिणाम त्रिपिंडीय पुनर्संयोजन से अलग थे क्योंकि तीसरे अणु को दो-परमाणु वाले अणु की ऊर्जा नहीं मिलने से बिना जोड़े वाला परमाणु जाल में फंस गया। इस प्रयोग में अपेक्षा से अधिक पुनर्संयोजन दर भी दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि इसने एक अणु बनाने में सैद्धांतिक गणनाओं की तुलना में अधिक वक्त लिया। इस असंगति की व्याख्या नहीं की जा सकती है जिसका मतलब है कि इसमें आगे शोध करने की काफी गुंजाइश मौजूद है।

रुबिडियम एक क्षारीय धातु है जिसकी परमाणु संख्या 37 है। यह अत्यधिक क्रियाशील, वायुमंडल में आग पकड़ने वाली धातु है। इसका मतलब है कि यह धातु प्रकृति में कभी भी पृथक रूप में नहीं पाई जाती है। इसका सर्वाधिक स्थायी समस्थानिक रुबिडियम-85 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह क्वांटम मैकेनिक से जुड़े प्रयोगों का पसंदीदा अवयव है। रुबिडियम पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स (बीईसी) में विस्तृत अध्ययन हो चुका है। बीईसी पदार्थ की वह खास अवस्था है जब बोसॉन को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। बोसॉन कण का नामकरण सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर किया गया था।

बीईसी के वजूद के बारे में सबसे पहले बोस एवं आइंस्टीन ने 1924 में संकल्पना पेश की थी लेकिन इसके स्वतंत्र अस्तित्व की पुष्टि 1995 में ही हो सकी जब रुबिडियम-87 समस्थानिक का एक बीईसी पहली बार बनाया गया। इसी खोज को आधार बनाते हुए 2001 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

बोस-आइंस्टीन आंकड़ों के मुताबिक एक बीईसी कई कणों को एक साथ कम ऊर्जा की समान स्थिति में गिरते हुए देखता है। 1995 के बाद रुबिडियम से संबंधित बीईसी आचरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। इससे इस अवयव की संलिप्तता वाली बहुल-पिंडी आणविक प्रक्रिया की एक समझ पैदा हुई है। लेकिन ओटागो यूनिवर्सिटी का नया शोध-पत्र कहता है कि एक ऑप्टिकल ट्वीजर जाल में त्रि-पिंडीय प्रक्रियाओं की संख्यात्मक व्याख्या को लेकर कोई भी विश्वसनीय सिद्धांत नहीं है। शोध टीम ने त्रि-पिंडीय अंत:क्रिया को देखकर यह समझा कि परमाणु उतनी तेजी से एकसूत्र में नहीं बंधते हैं जितना सैद्धांतिक मॉडल बताते हैं। इसे संभवत: क्वांटम प्रभाव माना जाता है लेकिन इसकी संतोषजनक व्याख्या के लिए नई अंतर्दृष्टि विकसित करने की जरूरत है।

इस प्रयोग के सैद्धांतिक निहितार्थों और अंतर्दृष्टि से अलग इस परीक्षण से पता चलता है कि अलग-अलग परमाणुओं के साथ छेड़छाड़ कर पाना संभव है। भविष्य में इसका नैनो-तकनीक पर बड़ा असर देखा जा सकता है।

कानाफूसी

बागी तेवर

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमल नाथ पर उनकी पार्टी के भीतर से नया हमला राज्य सरकार के लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री के अनधिकारिक सलाहकारों में वरिष्ठ अफसरशाहों का दबदबा है। उन्होंने लिखा कि वह इस बात से दुखी हैं कि वह किसी की पदस्थापना तक नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि अधिकारियों की मर्जी से होने वाली पदस्थापना का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद उन्होंने इंदौर में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि इंदौर जैसी आकर्षक जगहों पर नियुक्त अधिकारी पद पर इसलिए हैं क्योंकि उनकी कमल नाथ या उनके करीबियों तक सीधी पहुंच है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी अन्य राजनेता की भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री को अवश्य बताएंगे कि यह सरकार उन कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर रही है जिनकी 15 वर्ष की कड़ी मेहनत की बदौलत वह सत्ता में आई। वर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया जिन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से कहा था कि वह चिंता न करें, उन्हें और उनके साथियों को कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार हम चला रहे हैं। वर्मा की कटुता के बावजूद यह तय नहीं है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाएगी या नहीं।

आपका पक्ष

बैंकिंग सुधार की पहल तेज हो

आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में अग्रणी बैंकिंग सुधार है। इस सुधार पर आज तक मंद गति से ही काम चलता आया है। बैंकिंग सुधार में भी अहम निजी क्षेत्र के बैंकों की समाधान प्रक्रिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रिजर्व बैंक कमजोर और खस्ता निजी बैंकों की नीलामी पर फैसले नहीं ले पाता है। निजी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन में भी स्थानीय राजनीति अपना असर बराबर दिखाती है, क्योंकि बहुत से इनमें स्टेक होल्डर स्थानीय नेता होते हैं। लिहाजा केंद्रीय बैंक ऐसी नीलामी समयबद्ध कार्य योजना के अनुरूप नहीं कर पाता है। कमजोर निजी बैंकों की परिसंपत्तियां, परिचालन तथा देनदारियों के निपटान में वर्षों का विलंब उनके ग्राहकों के हित में नहीं होता है। उनके छोटे निवेशकों, शेयरधारकों को नुकसान होता है। इस मामले में वित्त मंत्रालय को अमेरिका से सबक लेना चाहिए। वहां ऐसे सारे समाधान एक स्वतंत्र एजेंसी करती है, वह अधिकार प्राप्त होती है। केवल अपने बूते पर रिजर्व बैंक ऐसे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

हिम्मत जोशी, नागपुर

जीडीपी का लगातार कम होना

आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) **सरकार को बैंकों में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है**

कम होकर महज 4.7 प्रतिशत रह गई है। भारत का जीडीपी पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिर रहा है। जीडीपी दर तकरीबन 8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन वैश्विक मंदी के दौर तथा भारत में आर्थिक सुस्ती की वजह से जीडीपी दर का गिरना चिंताजनक है। विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्र में सुस्ती आने के कारण भी जीडीपी दर में कमी की मुख्य वजह है। वैश्विक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा था जिस वजह से देश में खपत कम होने लगी थी। लोग बेवजह खरीदारी से बच रहे थे। इस वजह से भारत में भी आर्थिक सुस्ती छा गई थी। देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे वाहन उद्योग और रियल एस्टेट में सुस्ती छा गई थी। बेरोजगारी दर भी बढ़ने के कारण लोगों में खरीदारी करने की क्षमता घटी थी। एक दशक पहले भारत की जीडीपी दर 8 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। सरकार को आर्थिक सुस्ती कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

इस साल कृषि उपज बढ़ने के आसार

इस साल किसानों को अपनी उपज का काफी फायदा मिल सकता है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हाल में आई खबरों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में देश के कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें खरीफ सीजन में अच्छे उत्पादन और रबी सीजन में भारी पैदावार की संभावना है। यह किसानों को काफी फायदा पहुंचा सकता है लेकिन अक्सर देखा गया है कि अधिक फसल की पैदावार से किसानों को घाटा भी उठाना पड़ा है। कई बार ऐसे मौके आए हैं कि किसान अधिक उपज को सड़क पर फेंकने पर मजबूर हुए हैं। सरकार की उदासीनता के कारण उपज का सही दाम नहीं मिलने से किसान सड़क पर आलू, प्याज तथा कई सब्जियां भी फेंक चुके हैं। ऐसे में सरकार को अधिक पैदावार देखते हुए इसके भंडारण की उचित जगह तैयार करना चाहिए।

संदीप झा, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

अमेरिका और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ कर गए ट्रंप

दीपक शर्मा

भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सपरिवार भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रंप की छवि एक मनमौजी और बेबाक व्यक्ति की रही है, लेकिन भारत यात्रा के दौरान वह संयमित रहे। उन्होंने भारत-पाकिस्तान को अपने मामले सुलझाने को कहा, लेकिन मध्यस्थता की भी पेशकश कर दी। ट्रंप ने मोदी और इमरान दोनों को अपना मित्र बनाया, जो उनकी कूटनीति का हिस्सा है। अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री के लिए भारत को बहुत बड़ा बाजार समझता है। ट्रंप और मोदी की मित्रता भावनाओं पर कम और व्यवसायिक रिश्तों पर ज्यादा टिकी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसे ट्रंप के दौरे से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

डॉ. राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

नहीं मिला कुछ खास फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होने के आसार हैं, लेकिन यह समय ही बताएगा कि आने वाले समय में भारत के प्रति अमेरिका कैसा रुख कैसा रहता है। हमारे देश के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका की नीयत साफ नहीं नजर आती है। अमेरिका ने भारत को उस सूची से बाहर कर दिया है, जिसमें विकासशील देशों से आयात को प्रोत्साहन दिया जाता है। ट्रंप ने भारत पर यह आरोप भी लगाया है कि हमारा देश पिछले काफी समय से ऊंचे शुल्क से अमेरिका के व्यापार पर चोट कर रहा है। यही नहीं, इससे पहले भी हमारे देश के प्रति ट्रंप का प्रतिकूल रवैया देखने को मिला है। अमेरिका आतंकवाद के प्रति दोगली नीति अपनाता आया है। कुछ समय पहले ट्रंप ने पेरिस समझौते से भागने का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़कर अपना असली चेहरा दिखा दिया था।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे

विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस दौरे के दौरान व्यापार को लेकर भले ही कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका, लेकिन तीन अरब डॉलर के रक्षा समझौते को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारतीय हितों का ध्यान रखने का भरोसा जताया है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमेशा की तरह अमेरिका का साथ मिलता रहेगा। ट्रंप की यात्रा आपसी संबंधों को मजबूती देगी।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

ट्रंप की यात्रा से अमेरिका को फायदा

अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना मित्र बताता है, जबकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। भारत और अमेरिका के बीच तीन अरब डॉलर के हुए रक्षा सौदों में विभिन्न तरह के रक्षा उपकरणों की डील हुई जो कि भारत को रक्षा में और मजबूत बनाएगा। अमेरिका वही उपकरण पाकिस्तान को भी बेचेगा जिससे साफ जाहिर है कि उसका यह व्यवसाय है। इसके अलावा स्वास्थ्य, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गए सौदे भारत के लिए अच्छी रहेगी। ट्रंप के भारत आने का सबसे बड़ा मकसद था यह था कि वह फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और वह अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने के लिए भारत आए थे। कुल मिलाकर ट्रंप की यात्रा से अमेरिका और ट्रंप को ज्यादा लाभ हुआ है। भारत के लिए फायदा कम ही हुआ है।

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

दोनों देश ज्यादा करीब आएंगे

भारत और अमरीका ऐसे दो देश हैं, जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के बीच भिन्न-भिन्न सामरिक और विचारात्मक कारणों से समय-समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक-दूसरे के करीब आए हैं। हमारे देश की मौजूदा नीति राष्ट्रीय हितों के लिए एक साथ विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाने की है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहां आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण अपनी मित्रता की नीति के अनुसार विभिन्न देशों में जाकर व्यापार समझौते कर रहे हैं। ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक और सामरिक महत्त्व के समझौतों से दोनों राष्ट्रों के संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

हरमोहन नीमा
इंदौर, मध्य प्रदेश

एनआरआई को साध गए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने भारत-अमेरिकी संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस दौरे के दौरान घरेलू उत्पाद, सुरक्षा, बौद्धिक संपदा कानून, असैनिक परमाणु सौदे के तहत रिएक्टर समझौता, रक्षा सौदा और सीमित व्यापार शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने दुनिया के हालात और भारत अमेरिकी संबंध की संभावनाओं पर बातचीत की। ट्रंप के इस दौरे का एक मकसद अमेरिका में भारतीय मूल के लाखों मतदाता को साधना भी रहा है। भारत में संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों का चलन बढ़ रहा है। इसलिए ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार घाटे को दुरुस्त करना चाहते हैं। अब यह प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रंप को व्यापार समझौते को दुरुस्त करने की जिद छोड़ने और भारत अमेरिकी संबंधों के रणनीतिक संभावनाओं पर ध्यान देने के लिए कितना मना लेते हैं।

साक्षी पांडे
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

वैश्विक स्तर पर बढ़ा भारत का कद

अमेरिकी राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से ट्रंप ने एक तीर से कई शिकार वाली उक्ति को चरितार्थ किया है। अमेरिका में होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर ट्रंप की इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे करीब 40 लाख भारतीयों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाना भी था। इसके अलावा वह भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूर और आधुनिक बनाने की बात कहकर अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री का उद्देश्य भी हासिल करना चाहते थे। इसका फायदा आने वाले दिनों में अमेरिका को मिलेगा। ट्रंप की नजर भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश से कई व्यापारिक समझौते करने पर भी है। कुल मिलाकर ट्रंप की भारत यात्रा से भारत को फायदा हुआ है।

संजय डागा
इंदौर, मध्य प्रदेश

रक्षा समझौता फायदेमंद

अमेरिका भारत का अहम कारोबारी साझेदार रहा है। ट्रंप के भारत दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि तीन अरब डॉलर का रक्षा समझौता रहा है। इसके तहत सैन्य हैलिकाप्टरों सहित अन्य रक्षा उपकरण भारतीय सैना को प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में संप्रभुता को बनाए रखने व आतंकवाद से निपटने हेतु संकल्प पर पुन: मुहर लगाई है। दोनों देशों ने तस्करी व संगठित अपराधों पर लगाम लगाने हेतु सहमति जताई और बड़े व्यापार समझौते पर आगे बात करने का निर्णय भी लिया। इस प्रकार ट्रंप के भारत दौरे के बाद अमेरिका व भारत के बीच विकास व विश्वास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है।

डॉ. एम एस सिद्दीकी
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

रक्षा सहयोग बढ़ेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान तीन अरब डॉलर के रक्षा समझौते हुए हैं। इनसे भारत को अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान, रॉकेट, जहाज और ड्रोन प्राप्त होंगे। ट्रंप ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग की पेशकश की है। भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन में सहयोग का आश्वासन दिया है। ड्रग तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी गंभीर समस्याओं पर भी आम सहमति बनी है। ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, आतंकवाद से लड़ाई, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क समेत अनेक मसलों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। पश्चिम एशिया के हालात और चीन-पाकिस्तान के रवैये को लेकर भी दोनों देशों को आपसी सूझ-बूझ बढ़ाने की जरूरत है। एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका की उन्नति में भारतीयों की एक बड़ी भूमिका है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

अपना हित साधने आए थे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यह पहली भारत यात्रा है। उनका एवं उनके परिवार का इस देश के प्रति उत्साह और आकर्षण दिखाई दे रहा है। बहरहाल अमेरिका से इस मौके पर बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं की जानी चाहिए। उनसे मदद मांगने के लिए पाकिस्तान अवश्य मजबूर है भारत नहीं। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि वह किन कारणों से हमारे अतिथि बनना चाहते हैं। व्यापार-वाणिज्य तो दौरे का एक हिस्सा है जो एक तरफा न होकर द्विपक्षीय ही होगा। अमेरिका के चुनाव में भारत और अनिवासी भारतीय का समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है। महात्मा गांधी के प्रति उनका नत मस्तक होना उनके कुछ ऐसे ही इरादों का संकेत देता है।

हिम्मत जोशी
नागपुर, महाराष्ट्र

अमेरिकी मदद का आश्वासन

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान तीन अरब डॉलर के रक्षा समझौते हुए। तेल और गैस केलिए समझौता होना भारत के लिए लाभदायक है। ट्रंप ने कहा भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन में भी हम सहयोग के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोनों देश मिलकर लगाम लगाएंगे। ट्रंप की इस यात्रा में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसमें भारत को सर्वाधिक लाभ हो। ट्रंप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा पर हुए समझौतों से अगर सबक लिया जाए तो यह पता चलता है कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने हितों के साथ समझौता नहीं करता। अब देखना यह है कि इस यात्रा में अमेरिकी हित पूरा होता है या भारत का।

रूबी सिंह
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

रक्षा सौदा अहम, बाकी खास नहीं

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक समझौता होने तक व्यापार सौदे को लेकर चल रही मौजूदा बातचीत के जल्द पूरा करने का फैसला लिया है। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच तीन अरब डॉलर का रक्षा समझौता भारत के लिए सबसे अहम रहा। सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों ही देश काफी करीब आए।भारत की दृष्टिकोण से ट्रंप का भारत दौरा रक्षा क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो कुछ खास नहीं रहा है। भारत ट्रंप के इस दौरे से यह अपेक्षा करता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समस्या का समाधान हो जाए जिसमें भारत काफी हद तक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहा है।

अनुज तिवारी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

ट्रंप की यात्रा भारत के लिए रही फायदेमंद

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले ही यह पता था कि इस समय व्यापार समझौता नहीं हो सकता था क्योंकि कुछ भारत की चिंताएं हैं और कुछ अमेरिका की। आगे भी बहुत जल्द यह समझौता होने की संभावना नहीं है। ट्रंप की इस यात्रा से भारत को सबसे ज्यादा फायदा ऊर्जा समझौते से हुआ है। भारत की सबसे बड़ी समस्या भी ऊर्जा है और अच्छे पर्यावरण के लिए वाहनों में गैस ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे पास ना तो अपना तेल है और ना ही गैस है। भारत के लिए पश्चिम एशियाई देशों से ईंधन खरीदना व्यावहारिक नहीं दिख रहा है। इस लिहाज से अमेरिका के साथ ऊर्जा समझौता बहुत जरूरी और लाभदायक है। हालांकि ये समझौते देश में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में के दौरान हो गए थे। लेकिन अब इस यात्रा के बाद अमेरिका की गैस निर्यातक कंपनियां भारत को गैस मुहैया कराने ब्योरे को अंतिम रूप दे रही हैं। रक्षा सौदों के मामले में भारत को विविधता लानी है। इसलिए ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका से रक्षा सौदा किया, जो भारत के लिए फायदेमंद है। न्यूक्लियर शक्ति के मसले पर भी कुछ मुद्दों पर चर्चा भी अच्छी रही। ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा समझौते होने के खास मायने नहीं रहते। कुल मिलाकर ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में समझौते से भारत को लाभ होगा। जहां तक अमेरिका के साथ भविष्य में व्यापार समझौता का सवाल है तो मेरे हिसाब से भारत को कुछ मामलों खासकर मेडिकल उपकरण, कृषि में शुल्क कम करने पड़ेंगे। इसके बदले में भारत को अमेरिका से स्टील पर ऐंटी-डंपिंग शुल्क और जीएसपी के मामले में राहत मिल सकती है। व्यापार समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में समझौते होना है। जहां तक एच-1 बी वीजा में राहत का सवाल है तो अकेले भारत के लिए अमेरिका यह नहीं कर सकता।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

प्रो. मनोज पंत
निदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

रक्षा समझौता फायदेमंद, ट्रेड डील के लिए दबाव से बचें

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान रक्षा और ऊर्जा समझौते पर बात बनी। जिससे भारत को फायदा होने जा रहा है। इस यात्रा के दौरान व्यापार समझौता होने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। व्यापार समझौते के मामले में लगता है कि भारत दबाव में है। इस समझौते के माध्यम से ट्रंप फायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बात आगे जरूर बढ़ी है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे संकेत मिले हैं कि इस समझौते पर इस साल के अंत तक आगे बढ़ने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था में अभी मंदी की समस्या है। कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्र में भारतीय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए खास ताकत नहीं है। भारत आरसेप के मामले में भारतीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धी न होने के कारण ही आगे नहीं बढ़ा था। भविष्य में भी इस मामले में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। अमेरिका भारत का कृषि बाजार चाहता है। अमेरिका अपने यहां कृषि पर भारी सब्सिडी दे रहा है। भारत चाहता है कि अमेरिका पहले अपने यहां कृषि पर सब्सिडी घटाए। अमेरिका भी कह रहा है कि भारत भी सब्सिडी कम करे। लेकिन भारत के सब्सिडी देने का कारण किसानों के जीवनयापन से जुड़ा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के खासकर छोटे किसान बाजार में टिक नहीं पाएंगे। जबकि अमेरिका दूसरे देशों के बाजारों पर काबिज होने के उद्देश्य से सब्सिडी दे रहा है। भारत ने अमेरिका और यूरोप दोनों को सब्सिडी कम करने को कहा है। भारत सरकार दो साल से आयात शुल्क बढ़ा रही है। इसकी वजह बढ़ते आयात को नियंत्रित करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान रक्षा और ऊर्जा समझौते होना फायदेमंद रहा। अब भारत को आगे व्यापार समझौता करते समय शुल्क घटाने के लिए अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

डॉ. बिश्वजीत धर
ट्रेड विशेषज्ञ व प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) जेएनयू

पुरस्कृत पत्र

भारत को कम, अमेरिका को फायदा

भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति के बहुप्रतिक्षित दौरे से भारत को आर्थिक क्षेत्र में कई सकारात्मक उम्मीद थी। लेकिन यह दौरा भारत के आर्थिक हित की अपेक्षा अमेरिका के व्यापारिक हितों के रूप में ज्यादा परिलक्षित हुआ। अगर अमेरिकी संदर्भों में देखें तो उन्होंने कामयाबी से इस दो दिवसीय दौरे में तीन अरब डॉलर का रक्षा सौदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सौंप दिया गया, जबकि भारत ने रक्षा संबंधी उत्पाद के लिए निवेश किया। इस दौरे से भारत में अमेरिकी निवेश के तौर पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। आर्थिक सुस्ती के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। किंतु इस दौरे पर ऐसी किसी भी व्यापारिक साझेदारी का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ जिससे भारतीय हितों को मजबूती मिले।

डॉ महेश बंसिया
उज्जैन, मध्य प्रदेश

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

रवींद्र प्रकाश
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

संबंधों को नया आयाम

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम मिला है। इस यात्रा से विश्व को एक संदेश दिया गया है कि भारत और अमेरिका वैचारिक स्तर पर दो विपरीत ध्रुव नहीं है। अपनी छवि के विपरीत ट्रंप ने नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर संतुलित व्यवहार अपनाया। ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। इस यात्रा के दौरान भारत के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारतीय सेना को शक्ति मिलेगी। इस दौरान ऊर्जा संबंधी कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और मिलकर काम करने की सहमति भी बनी। कुल मिलाकर ट्रंप की यात्रा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी।

सूर्यभानु बांधे
रायपुर, छत्तीसगढ़

सुरक्षा पर एकमत

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की पहली भारत यात्रा के दौरान तीन अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुए। साझा बयान में दोनों देशों के बीच हुए तीन समझौतों का जिक्र था। इनमें एक ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर था। साझा बयान में इस पर भी सहमति जताई गई कि दोनों देश बड़े व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक रिश्तों के दायरे को वैश्विक स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर जो प्रतिबद्धता जताई गई, उससे रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बल मिलेगा। दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समेत तीन सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। यह संकेत है कि भारत-अमेरिका संबंध द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय आयामों से आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर सम्मिलित हित की मंशा रखते हैं।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

अहम रही यात्रा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से देखना उचित नहीं होगा। लेकिन परोक्ष रूप से इस दौरे से कई सकारात्मक पहलू दिखाई देते हैं, चाहे वह अमेरिका से तेल की आपूर्ति से खाड़ी देशों की निर्भरता कम होना हो, रक्षा उत्पादों व प्रौद्योगिकी के आयात के लिए राह हो या अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में साख रखने वाले दोनों देशों के साथ में काम करने की आशा हो। एक ऐसे देश जिसके संबंधों के लिए दुनिया लालायित रहती है वहां का राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा करके स्वागत के लिए कृतज्ञता प्रकट करे, यह कूटनीतिक स्तर पर उपलब्धि से कम नहीं। लिहाजा उसमें भले ही अमेरिका के बड़े बाजार व भारतीय अमेरिकी वोटरों को साधने जैसे हित साध रहे हों।

एम राज राकेश
अलवर, राजस्थान

भारत को फायदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा दिखावटी तौर पर औपचारिक कही जा सकती है। लेकिन यथार्थ में इसे रणनीतिक मुद्दों की साझेदारी और सहयोग की समझा जाएगा। कारोबारी दृष्टिकोण से अमेरिका भारत के टैरिफ को सही नहीं मानता फिर भी यह यात्रा फलदायी ही प्रमाणित होगी। ट्रंप ने इस यात्रा के दौरान भारत के साथ तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदे की घोषणा की जो भारत के लिए लाभदायक है। भारत में 200 से अधिक अमेरिकी कंपनियां हैं। आगे और भी निवेश बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में लाखों की संख्या में अनिवासी भारतीय मतदाताओं को देखते हुए ट्रंप के लिए चुनावी साल में भारत यात्रा महत्त्वपूर्ण है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का मूलभूत मुद्दा अछूता रह गया।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है –
कोरोनावायरस का देसी कारोबार पर असर?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

कोरोना बना लेखवाकारों के लिए मुश्किल

सुदीप्त दे

ऐसे समय में जब अधिकांश कंपनियां अपने सालाना वित्तीय नतीजों को तैयार करने और खातों के मिलान के लिए जूझ रही हैं, कारोबार पर कोरोनावायरस के प्रतिकूल प्रभाव ने लेखा परीक्षकों और लेखाकारों की परेशानी बढ़ा दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे अहम चुनौती वर्तमान और भविष्य में परिसंपत्तियों, देनदारी और नतीजों पर इसके संभावित वित्तीय प्रभाव का आकलन करना है। इसके अलावा आगे आने वाले कारोबारी परिदृश्य के बारे में विभिन्न पक्षों को सटीक जानकारी देना भी एक बड़ी चुनौती है।

जो कंपनियां आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हैं या जिनका चीन के बाजार में निवेश है, वे कोरोनावायरस के प्रकोप से सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। एनए शाह एसोसिएट्स में पार्टनर मिलन मोदी ने कहा, 'चीन से जुड़े निवेश, ऋण और परिसंपत्तियों को नुकसान के लिए अतिरिक्त परीक्षण से गुजरना पड़ सकता हैं।' उन्होंने साथ ही कहा कि देनदारी के मोर्चे पर प्रतिबद्धता, दायित्व और चीन से सामान की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुए नुकसान को भी वित्तीय नतीजों में शामिल करने की जरूरत है।

एसआर बाटलीबॉय ऐंड एसोसिएट्स के एश्योरेंस सर्विसेज के पार्टनर एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिस डायरेक्टर गोविंद आहूजा कहते हैं, 'जिन भारतीय कंपनियों की कोरोनावायरस से प्रभावित बाजारों में मौजूदगी है, उन्हें अपनी नकदी या फंडिंग जरूरतों की समीक्षा करनी होगी। उन्हें इन्वेंट्री की वसूली और प्राप्तियों पर दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।'

सिफी टेक्नोलॉजिज के मुख्य वित्त अधिकारी एमपी विजय कुमार के मुताबिक चीन में निवेश वाली अधिकांश भारतीय कंपनियों ने 'फोर्स मेज्योर' अनुबंध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह ऐसा अनुबंध है जो कंपनियों को प्राकृतिक और अपरिहार्य आपदाओं से पैदा हुए दावों से बचाता है। कई वर्षों से विभिन्न देशों में वित्तीय नियामक ऐसी अहम राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं पर सुझाव जारी करने के लिए सक्रिय रहते हैं जिनका वित्तीय नतीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीएओबी) और ब्रिटेन के फाइनैंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल की लेखाकारों और अन्य पक्षों के साथ कई दौर की वार्ता हुई है। इन वार्ताओं में इस बात पर चर्चा हुई कि वित्तीय नतीजों में वायरस के प्रकोप के प्रभाव को किस तरह शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कंपनियों और लेखाकारों को सुझाव दिया है कि वित्तीय नतीजों पर वायरस के असर पर नजर रखी जाए और सभी पक्षों को समय-समय पर उचित जानकारी दी जाए। ये नियामक कंपनियों को उनकी स्थिति के आधार पर खास राहत देने के लिए भी तैयार हैं।

मोदी के मुताबिक सबसे बड़ी नियामकीय चिंता यह है कि कंपनियां अपने कारोबार पर कोरोनावायरस के संभावित असर और जोखिम आकलन के बारे में सही-सही जानकारी नहीं देंगी। उनका कहना है कि भारतीय नियामकों को भी सामान्य मुद्दों पर लेखाकारों को सुझाव जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बातचीत से एकीकृत वित्तीय नतीजों को सौंपने की समयसीमा के बारे में स्पष्टता आएगी।'

विजय कुमार को लगता है कि जो कंपनियां कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, उनके निदेशक मंडलों को अपने निवेशकों और बैंकरों के साथ सक्रियता के साथ संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर आप समय पर सही जानकारी देते हैं तो सभी पक्ष इसे सकारात्मक ढंग से लेते हैं।' हालांकि वह कंपनियों को अपने संचयी वित्तीय नतीजे सौंपने में अतिरिक्त समय देने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन उन कंपनियों के मामलों में ऐसा किया जा सकता है जिनकी सहयोगी कंपनियां या संयुक्त उपक्रम कोरोनावायरस प्रभावित देशों में है।

भारतीय कंपनियों की अहम समस्याएं

- कोरोनावायरस से प्रभावित कई भारतीय कंपनियों ने खुद को दावों से बचाने के लिए फोर्स मेज्योर अनुबंध लागू करना शुरू कर दिया है
- जिन कंपनियों की चीन या अन्य प्रभावित देशों में सहयोगी कंपनियां या संयुक्त उपक्रम हैं, उनके लिए वित्तीय नतीजे तैयार करना या उन्हें ऑडिट कराना एक चुनौती होगी
- आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता और दूसरे पक्षों से ऑर्डर की पुष्टि नहीं मिलने से वित्तीय रिपोर्ट बनाने में समस्याएं आ रही है
- उत्पादन चक्र और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान से इन्वेंट्री और सीमित अवधि की दूसरी परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना पड़ सकता है

कैसे निपट रहे हैं अन्य

अमेरिका

- एसईसी और पीसीएओबी ने इस बारे में देश की बड़ी ऑडिट कंपनियों के साथ चर्चा की है कि वित्तीय नतीजों और ऑडिट क्वालिटी पर इसका क्या असर हो सकता है
- कंपनियों को अपनी लेखा समितियों और लेखाकारों के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया गया है ताकि उनकी वित्तीय जानकारी, ऑडिटिंग और समीक्षा प्रक्रियाएं सुदृढ़ हों
- कंपनियों को राहत और सुझाव के लिए एसईसी के कर्मचारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया गया है
- एसईसी परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग मामलों में राहत पर विचार कर सकता है

(एसईसी और पीसीएओबी के 19 फरवरी के संयुक्त बयान पर आधारित)

ब्रिटेन

- अपनी सालाना रिपोर्ट बनाते हुए कंपनियों को अप टु डेट और सार्थक जानकारी देनी चाहिए
- यह उन कंपनियों के लिए प्रासंगिक है जो चीन में काम कर रही हैं या चीन से होने वाले आयात पर निर्भर हैं या जिनके चीन के साथ करीबी कारोबारी संबंध हैं
- कंपनियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्हें कारोबार पर संभावित जोखिम और अनिश्चितताओं के बारे में वित्तीय नतीजों में जानकारी देनी चाहिए या नहीं
- उन्हें इसके असर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने की भी जरूरत है और साथ ही परिसंपत्तियों और देनदारी के मूल्य की भी जानकारी देनी चाहिए

(एफआरसी के 17 फरवरी के बयान पर आधारित)

चीन के 100 से अधिक उत्पादों पर लगेगा शुल्क!

शुभायन चक्रवर्ती

दुनिया भर में कोरोनावायरस से महामारी फैलने के मद्देनजर वाणिज्य विभाग जल्द ही एक सौ से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के संबंध में निर्णय ले सकता है। भारत इन उत्पादों का भारी मात्रा में चीन से आयात करता है। इस सप्ताह विभाग की उद्योग जगत के संगठनों के साथ बैठक करने की संभावना है और इसमें आयात शुल्क पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच, अधिकारियों ने इन खबरों को अफवाह बताया कि कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के लिए चीन अपने बंदरगाहों और कंटेनर की आवाजाही बंद करने पर विचार कर रहा है।

कुल मिलाकर सरकार पसोपेश की स्थिति में है। एक तरफ सरकार मांग से जुड़ी प्राथमिकताएं साधने पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार को चीन के उत्पादों से बचाने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इस समय चीन में कोरोनावायरस के कारण का उत्पादन प्रभावित हुआ है और भारत इस मौके लाभ उठाकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ाव देना चाह रहा है। हालांकि कई वस्तुओं का विनिर्माण देश में क्षमता अभाव के कारण सीमित स्तर पर हो रहा है। इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ऐसे समय में आयात बढ़ाना काफी पेचीदा हो सकता है। अगर परिस्थितियां जल्द नहीं सुधरीं और औद्योगिक जिंसों की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं तो बढ़े आयात शुल्क का ग्राहकों और वृद्धि दर दोनों पर प्रतिकूल असर हो सकता है।'

> सरकार भारतीय बाजार को चीन के उत्पादों से बचाने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगाह किया है कि बुनियादी जरूरत वाली जिंसों की खेप अटकने के बाद थोक एवं खुदरा स्तर पर इनके भंडार में कमी आ रही है। संगठन के अनुसार अगर परिस्थितियों में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ, औद्योगिक संगठनों ने यह भी कहा है कि आयातक मध्य जनवरी से ही नए ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। भारत चीन से 70 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है। हालांकि इसके बावजूद आयातकों का एक बड़ा समूह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आयात के ऑर्डर देने के लिए चीन के विनिर्माण केंद्रों में नियमित तौर पर जाता है। कोरोनावायरस के बाद आयातक चीन नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उन्हें डर है कि परिस्थितियां सामान्य होने के बाद दूसरे देशों के आयातक अपने ऑर्डरों के लिए जोर लगाना शुरू कर देंगे।

आयात पर रोक नहीं

इस बीच, ऐसी अटकल चल रही है कि चीन 1 मार्च से एक या अधिक प्रमुख बंदरगाह बंद कर सकता है। ऐसी अटकलों से घरेलू उद्योग जगत में चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के स्थानीय मीडिया के अनुसार कोरोनावयरस के प्रसार के बाद शांघाई और यांगशन सहित वहां के प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों का पहुंचना पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले जनवरी में 17 प्रतिशत तक कम हो गया। वरिष्ठ अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों ने कहा कि दूसरे देशों ने चीन से आयात सीमित कर दिया है, लेकिन चीन की सरकार ने बंदरगाह बंद करने की अब तक घोषणा नहीं की है।

चीन दुनिया में कंटनेरों का परिचालन करने वाला सबसे बड़ा देश है। वैश्विक वित्तीय बाजार एवं अधोसंरचना से जुड़े आंकड़े मुहैया करने वाली रिफीनिटिव ने कहा कि चीन ने 2019 में दुनिया में कंटनेरों की कुल आवाजाही में 30 प्रतिशत तक योगदान दिया था। द इंटरनैशनल चैंबर ऑफ शिपिंग ने हाल में कहा कि कोरोनावायरस की रोकथाम के कुछ उपाय कर चीन में बंदरगाहों पर परिचालन जारी रखा जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार ने मई तक सभी बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर सीमा शुल्क निपटान सुविधा चौबीस घंटे खुला रखने का आदेश दिया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन अजित कुमार ने सभी मुख्य आयुक्तों (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर) को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी बंदरगाहों, माल पड़ावों (कार्गो स्टेशनों), इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ परिस्थितियों के तहत दस्तावेज के आने में देरी पर लगने वाले विलंब शुल्क भी माफ किए जाएंगे।

कोरोना की गिरफ्त में बाजार

पृष्ठ 1 का शेष

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पिछले हफ्ते शेयर बाजार से 12,000 करोड़ रुपये की निकासी की। घरेलू निवेशकों ने इससे ज्यादा रकम निवेश किया लेकिन गिरावट को थामने में विफल रहे।विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवली बनी रह सकती है और केवल दीर्घावधि तक निवेश करने वाले निवेशक ही अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तक निवेश बनाए रख सकते हैं।हालांकि बाजार के भागीदार शॉर्ट कवरिंग जैसे तकनीकी कारकों की वजह से बाजार की वापसी की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहा है कि दीर्घावधि वाले निवेशक गिरावट पर खरीद कर सकते हैं क्योंकि केंद्रीय बैंकों और सरकार की नीतियों से बाजार को राहत मिल सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दर में कटौती के भी संकेत दिए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी एस नरेन ने कहा, 'ऐतिहासिक तौर पर बाजार में जब भी गिरावट आती है तो वह निवेश का आकर्षक मौका होता है। लेकिन यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा संकट कब तक बना रहेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में निवेश करते समय किस्तों में निवेश करना चाहिए।'

वैश्विक बाजारों पर नहीं दिखा पूरा असर

भारत समेत वैश्विक वित्तीय बाजारों में कोरोनावायरस का असर दिखा है। रोजर्स होल्डिंग्स के चेयरमैन **जिम रोजर्स** ने **पुनीत वाधवा** के साथ साक्षात्कार में बताया कि इसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर असर दिखना बाकी है। उनसे बातचीत के मुख्य अंश:

कोरोनावायरस से उत्पन्न विश्वव्यापी महामारी की पृष्ठभूमि में वैश्विक वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहेगा?

कोरोनावायरस वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहा है। पूरी दुनिया में हवाई अड्डों, होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लोगों की उपस्थिति घटी है। कोरोनोवायरस के प्रसार से पहले भी सुस्ती की मार झेल रही चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। ताजा घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि हालात और बदतर हो सकते हैं। चीन में दिवालियापन की स्थिति से हालात खराब हो सकते हैं। मेरा मानना है कि यह उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा, जो इस तरह की आशंका नहीं देख रहे हैं। जहां तक कोरोनावायरस का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि बाजारों में इसका प्रभाव पूरी तरह से दिखा है। पिछले एक या दो सप्ताह में भी, कई वैश्विक बाजार ऊंचाई के साथ कारोबार कर रहे थे और सिर्फ पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में ही उनमें गिरावट देखी गई है। कई वित्तीय बाजार कोरोनावायरस के प्रभाव को लेकर आश्चर्यचकित हुए हैं और यह प्रभाव बाजारों पर पूरी तरह से नहीं दिखा है।

क्या इस महामारी का बाजारों पर प्रभाव दिख चुका है?

नहीं। मेरा मानना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों पर इसका असर दिखना बाकी है- पूरी तरह से कोरोनावायरस की वजह से नहीं बल्कि वृद्धि की धीमी रफ्तार से भी दबाव बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस के प्रसार से पहले भी धीमी गति से बढ़ रही थी, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम तेजी दर्ज नहीं करेंगे। दुनियाभर में देशों के पास पर्याप्त पूंजी है और वे इसे खर्च भी कर रहे हैं।

यदि कोरोनावायरस का प्रभाव अनुमान के मुकाबले ज्यादा रहा तो क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है?

ऐसा शायद कोरोनावायरस की वजह से नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि चीन में इस वायरस का प्रभाव चरम पर है और उन्होंने कुछ काफी मजबूत कदम भी उठाए हैं। हालांकि वायरस के परिणामस्वरूप, लोगों और कंपनियों के दिवालिया होने जैसी स्थिति से कुछ महीनों में मंदी गहराने का खतरा पैदा हो सकता है।

कारोबारी कानून

लॉयल्टी बीमे से बचा कंपनी का नुकसान

अदालत से

एमजे एंटनी

उच्चतम न्यायालय ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को नैशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन को 3.5 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। कंपनी को उसके अपने कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से नुकसान हुआ था। कॉरपोरेशन ने फिडेलिटी गारंटी बीमा लिया था। किसी कंपनी या संस्था के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, चोरी और अन्य अपराध इस पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इसके तहत बीमा ईमानदारी के लिए, लापरवाही के खिलाफ या अपने कर्मचारियों के प्रति वफादारी के लिए होता है। इसके तहत जो संरक्षण होता है, वह सामान्य बीमा पॉलिसियों से अलग होता है। इस मामले में कॉरपोरेशन एक रेहन प्रबंधन कंपनी थी, जो किसानों, कारोबारियों और विनिर्माताओं द्वारा बैंकों से कर्ज लेने के लिए जमानत पर रखी गई वस्तुओं का भंडारण करती है। दावे की नौबत तब आई जब पता चला कि उधमपुर के एक गोदाम में रखा गया 601 बैरल मेंथा ऑयल की जगह पानी रख दिया गया था। कॉरपोरेशन ने फिडेलिटी पॉलिसी के तहत मुआवजे का दावा किया। उसने आरोप लगाया कि उसके कर्मचारी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। कॉरपोरेशन ने इस बारे में पुलिस में भी शिकायत दर्ज की थी। हालांकि बीमा कंपनी ने दलील दी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कर्मचारियों ने यह धोखाधड़ी की क्योंकि बैरलों की सील जस की तस थी। न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी पॉलिसी में कवर थी।

बीमा के लिए ग्लाइडर को माना जाएगा विमान

उच्चतम न्यायालय ने एक बीमा कंपनी को एक युवा की मां को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस युवक की कनाडा में ग्लाइडर की यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। युवक ब्रिटिश कोलंबिया में दो सीटों वाले ग्लाइडर में सवार था तभी एक सेसना विमान उससे टकरा गया। इससे युवक और ग्लाइडर के पायलट की मौत हो गई। बीमा कंपनी ने यह कहकर दावे को खारिज कर दिया कि ग्लाइडर यात्रियों को ले जाने वाला मानक विमान नहीं है और इसलिए वह बीमा के दायरे में नहीं आता है। कंपनी ने साथ ही दलील दी कि युवक राउंड ट्रिप पर था और उसका कोई गंतव्य नहीं था। इसलिए वह यात्री नहीं था। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और न्यायालय ने बीमा कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया और व्यवस्था दी कि विमान कानून के मुताबिक ग्लाइडर एक विमान है। एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रिया पॉल वाद में न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी ने ग्लाइडर को देनदारी से बाहर नहीं रखा है जबकि खासतौर पर हैंड-ग्लाइडिंग, बैलूनिंग, पैराशूटिंग और दूसरे रोमांचक खेलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा कि युवक ग्लाइडर पर सवार (चार्टर) हुआ था। चार्टर शब्द भारत और कनाडा के कानूनों में परिभाषित नहीं है। अगर इसके अर्थ को लेकर कुछ अस्पष्टता है तो इसकी व्याख्या से बीमित व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। न्यायालय ने साथ ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना गंतव्य के राउंड ट्रिप पर जा रहा है, तो भी वह यात्री है। ठीक उसी तरह जैसे कोई यात्री पर्यटक स्थलों की सैर कराने वाली बस में यात्रा करता है। यह बस उसी बिंदु पर वापस आती है जहां से वह यात्रा शुरू करती है।

हर अपील के साथ बढ़ती जाती है मुआवजा राशि

सड़क हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को हुए नुकसान का अंदाजा लगाना न्यायाधीशों के लिए मुश्किल होता है लेकिन ऐसा लगता है कि हर अपील पर मुआवजा बढ़ता जाता है। काजल बनाम जगदीश कुमार वाद में 12 साल की छात्रा जिंदगीभर के लिए पूरी तरह अपाहिज हो गई। जिस वाहन में वह यात्रा कर रही थी उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोटर दुर्घटना मुआवजा पंचाट ने उसे 11 लाख रुपये का मुआवजा दिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील पर इस राशि को बढ़ाकर 25.78 लाख रुपये कर दिया। आगे अपील पर उच्चतम न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतों ने मुआवजा तय करने में गलती और यह मोटर वाहन कानून के अनुरूप वाजिब राशि नहीं थी। न्यायालय ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 62.27 लाख रुपये कर दी। न्यायालय ने कहा कि बच्ची के वयस्क होने तक इस राशि को किसी सरकारी बैंक में सावधि खाते में जमा किया जाना चाहिए। इस पर मिलने वाले ब्याज से बच्ची की देखभाल करने वालों और इलाज के खर्च का भुगतान किया जाना चाहिए।

जबरन वसूली नहीं होनी चाहिए जब्ती

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि किसी काम का नियोक्ता कार्य अनुबंध में जब्ती की शर्त शामिल कर सकता है लेकिन यह व्यावहारिक होनी चाहिए, दंडात्मक या जबरन वसूली करने वाली नहीं। निविदा निकालने वाली सरकारी कंपनी की यह अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि उसे जमानत राशि की जब्ती करते समय संतुलन कायम करना चाहिए। न्यायालय ने आरबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम राइट्स लिमिटेड वाद में अपने फैसले में यह बात कही। इस मामले में दामोदर घाटी निगम ने एक सड़क परियोजना के लिए राइट्स को अपने साथ जोड़ा था। राइट्स ने निविदाएं आमंत्रित कीं और आरबीएल ने इसके लिए बोली लगाई। लेकिन उसने स्वीकृति दस्तावेज में कुछ चीजों को छिपाया था जो पेशकश की शर्तों का उल्लंघन था। इसलिए राइट्स ने जमानत की पूरी 50 लाख राशि जब्त करने का प्रयास किया जिससे मामला अदालत पहुंच गया। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक लागू करने योग्य समझौता था और शर्तों का उल्लंघन साबित हुआ था जो सवालों से परे था। लेकिन इसकी वजह से राइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब्ती से सरकारी को अप्रत्याशित फायदा नहीं मिलना चाहिए। उसे अनुचित तरीके से अपना खजाना नहीं भरना चाहिए क्योंकि ठेकेदार कंपनियों को सरकारी नियोक्ताओं के पास काम के लिए आवेदन करना पड़ता है।

कानूनी दांवपेच में फंसी मध्यस्थता

बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ के एकल पीठ के आदेश को खारिज करने के बाद कानूनी दावपेच में फंसा मध्यस्थता का एक मामला 12 साल बाद फिर शुरू होगा। एंटीकेरोस शिपिंग कॉरपोरेशन बनाम अदाणी एंटरप्राइजेज वाद में लाइबेरिया की जहाजरानी कंपनी ने आरोप लगाया कि भारतीय कंपनी द्वारा आपूर्ति किया गया ईंधन गुणवत्ता और मात्रा के अनुरूप नहीं था। उसने मध्यस्थता का सहारा लिया लेकिन इसमें कई सवाल शामिल थे। जैसे यह घरेलू मध्यस्थता होगी या अंतरराष्ट्रीय और अगर एक पक्ष नॉमिनी नियुक्त नहीं करता है तो उच्च न्यायालय को मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है या नहीं। यह विवाद सात साल तक चला और एकल पीठ ने अदाणी के पक्ष में आदेश दिया। जहाजरानी कंपनी ने इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की जिसने अदाणी की अपीलों के बारे में कुछ दिलचस्प टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना तीर और टॉरपीडो से की। अदाणी पर कानूनी खर्च के तौर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए न्यायालय ने कहा, 'प्रतिवादी द्वारा दागी गई टॉरपीडो बेकार गया और यह अपने लक्ष्य को साधे बिना डूब गया।'

सीमा शुल्क के रिफंड के लिए संघर्ष कर रही ओएनजीसी

उच्चतम न्यायालय ने सरकार और उसकी कंपनियों के अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने की प्रवृत्ति की आलोचना की है लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है जिसमें ओएनजीसी और केंद्र सरकार के बीच सीमा शुल्के के विवाद का निपटारा किया गया है। ओएनजीसी ने हाइड्रोकार्बन के उत्खनन के लिए रूस से कुछ उपकरणों का आयात किया और सीमा शुल्क 1986 में चुकाया गया। लगभग 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान था जो कि देय था। लेकिन कांडला बंदरगाह के अधिकारी रिफंड से मुकर गए। उनका तर्क था कि ओएनजीसी ने इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया था। अदालत ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इस मामले में कोई उपभोक्ता नहीं था और इस मांग को खारिज किया जाना चाहिए। ओएनजीसी की दलील सुनने के बाद अदालत ने अधिकारियों को ब्याज के साथ बकाये की गणना के लिए 30 दिन का समय दिया। न्यायालय ने भुगतान के लिए ज्यादा समय देने की अधिकारियों के अनुरोध को खारिज कर दिया क्योंकि इस मामले में पहले ही बहुत देरी हो गई थी।

स्पेशियलिटी केमिकल खंड के लिए मजबूत परिदृश्य

चीन में आपूर्ति से संबंधित बदलाव, नए ऑर्डर और विस्तार प्रमुख सकारात्मक घटनाक्रम हैं

उज्ज्वल जौहरी

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में स्पेशियलिटी केमिकल सेगमेंट मजबूत बना हुआ है। यह सेगमेंट नए ऑर्डरों और क्षमताओं में वृद्धि दर्ज कर रहा है।

नियमित ऑर्डर प्रवाह के अलावा, वैश्विक रसायन क्षेत्र में रुझान से भी भारतीय कंपनियों के लिए अल्पावधि अवसर बढ़ने की संभावना है। विस्तार, विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों, और नई उत्पाद पेशकशों को देखते हुए विश्लेषकों का मानना है कि इन कंपनियों के शेयरों में मौजूदा स्तरों से और तेजी आ सकती है।

सूचीबद्ध स्पेशियलिटी केमिकल कंपनियों ने निवेशकों के लिए लगातार कमाई के अवसर प्रदान किए हैं। बाजार को राजस्व वृद्धि और मार्जिन में सुधार की मदद से परिचालन प्रदर्शन में तेजी आने का अनुमान है। पिछली तिमाही भी इससे अलग नहीं रही। हालांकि राजस्व वृद्धि धीमी थी, क्योंकि रसायन कीमतों में गिरावट आई, लेकिन परिचालन मुनाफा वृद्धि दो अंक में बनी रही।

आईआईएफएल में विश्लेषकों का कहना है कि एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन और नियोजेन जैसी स्पेशियलिटी केमिकल कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्हें वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में अपस्ट्रीम कंपनियों को कोरोनावायरस महामारी का फायदा मिल सकता है।

चीन में कोरोनावायरस की वजह से

वहां से आपूर्ति बाधित हुई है। इस वजह से रसायन कीमतों में तेजी आ रही है, जो भारतीय रसायन कंपनियों के लिए लाभदायक है। शेयरखान में विश्लेषक रिषभ बोथरा का कहना है कि इसके अलावा, वैश्विक कृषि और स्पेशियलिटी रसायन कंपनियां भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के तौर पर देख रही हैं।

जिस वजह से चीन की तुलना में भारतीय कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गई हैं, वह है सस्ती कीमत पर कुशल श्रम की उपलब्धता। गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स और फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां एफएमसीजी, होम एवं पर्सनल केयर, और फूड इंग्रिडिएंट्स सेगमेंट की जरूरतें पूरी कर रही हैं। उनके विशिष्ट बिजनेस मॉडल और ऊंचे स्तर के उत्पाद अनुकूलन मजबूत एंट्री बैरियर्स सुनिश्चित करता है।

परिचालन में मजबूत सुधार

करोड़ रु.	शुद्ध बिक्री	बदलाव % सालाना	एबिटा	मार्जिन %	शुद्ध लाभ	बदलाव% सालाना
एसआरएफ	8,870	17.5	1,860	21.0	979	14.8
पीआई इंड.	4,406	26.6	953	21.6	640	29.1
आरती इंड.	5,526	19.6	1,242	22.5	696	24.0
अतुल	4,882	14.1	1,041	21.3	701	7.6
विनती	1,345	23.3	494	36.7	372	12.7
नवीन	1,265	17.1	327	25.9	235	24.7

वित्त वर्ष 21 के अनुमान, स्रोतः ब्लूमबर्ग

इसके अलावा, कच्चे माल की उपलब्धता के संदर्भ में भी ये कंपनियां अच्छी स्थिति में हैं। घरेलू आपूर्ति के अलावा, भौगोलिक स्थिति का भी इन्हें लाभ मिला है, क्योंकि इनकी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से नजदीकी है, जो प्रतिस्पर्धी आयात सुनिश्चित करते हैं।

स्पेशियलिटी केमिकल कंपनियों के लिए बाजार धारणा हाल में मजबूत हुई है, क्योंकि नवीन फ्लोरीन को फ्लूरोकेमिकल्स क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन वाले उत्पाद की आपूर्ति और निर्माण के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से 2,900 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इससे भारत को नाइश केमिकल से संबंधित दीर्घावधि अनुबंधों के लिए पसंदीदा देश के तौर पर मजबूती मिल सकती है।

इस क्षेत्र का मजबूत परिदृश्य प्रमुख कंपनियों द्वारा घोषित पूंजीगत खर्च योजनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखा है। इससे अगले चरण के विकास के लिए आधार मिलेगा। जहां नवीन फ्लोरीन को प्राप्त बड़े ऑर्डरों को देखते हुए 450 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च करना है, वहीं आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस भी क्षमता विस्तार कर रही हैं। आरती इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2020 के लिए 1,000 करोड़ रुपये की खर्च प्रतिबद्धता के बाद वित्त वर्ष 2021 में भी अन्य 700-800 करोड़ रुपये लगाएगी। अन्य कंपनियों ने 500 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत खर्च प्रतिबद्धताएं जताई हैं।

एडलवाइस रिसर्च में विश्लेषकों के लिए आकर्षक मूल्यांकन को देखते हुए प्रमुख कंपनियों में आरती इंडस्ट्रीज पसंदीदा बनी हुई है। निवेशक गिरावट पर एसआरएफ, फाइन ऑर्गेनिक्स, और गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स में निवेश कर सकते हैं।

बाजार हलचल

ग्रे बाजार में एसबीआई काड्र्स की बढ़त कमजोर

एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के लिए ग्रे बाजार में तेजी कुछ हद तक धीमी पड़ती दिख रही है। शेयर बाजार में पिछले सप्ताह की 7 प्रतिशत की गिरावट के बाद इसमें यह नरमी आई है। ग्रे बाजार के कारोबारी क्रेडिट कार्ड कंपनी को 400 रुपये प्रति शेयर जैसी ऊंची कीमत पर खरीद रहे थे। यह कीमत अब घटकर 300 रुपये प्रति शेयर से नीचे रह गई है। अभी भी 755 रुपये प्रति शेयर के अपर-बैंड निर्गम भाव की तुलना में यह 45 प्रतिशत की शानदार तेजी है। बाजार कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा जोखिम की धारणा से आईपीओ के लिए मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि निवेश बैंकरों का कहना है कि उन्हें संस्थागत निवेशकों से मजबूत प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है और इस निर्गम के सफल रहने की उम्मीद है। सोमवार को खुल रहा 10,355 करोड़ रुपये का यह आईपीओ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्गम है। *- समी मोडक*

एचडीएफसी लाइफ में आ रही तेजी

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में इस उम्मीद से अच्छी तेजी आई है कि निफ्टी सूचकांक में पहली बीमा कंपनी जगह बना रही है। बड़े फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण (सूचकांक में शामिल होने के लिए प्रमुख मानक) के बावजूद निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी डेरिवेटिव्स क्लब का हिस्सा कभी नहीं रही। निफ्टी का हिस्सा बनने के लिए यह भी जरूरी है कि शेयर एफऐंडओ खंड में कारोबार करे। इसकी शुरुआत के साथ एचडीएफसी लाइफ पर आधारित एफऐंडओ अनुबंध में कारोबार होगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि अगले बदलाव के दौरान यह शेयर 50 शेयर वाले ब्लू चिप इंडेक्स में जगह बना सकता है। *- समी मोडक*

बड़े परामर्शदाता दे रहे विलय पर ध्यान

बड़े संपत्ति आकार वाले स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार (आईएफए) अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए विलय की संभावना देख रहे हैं। एक आईएफए ने कहा, '200-400 करोड़ रुपये के परिसंपत्ति आधार वाले व्यक्तिगत म्युचुअल फंड (एमएफ) वितरक अन्य कंपनियों के साथ अपने व्यवसाय के विलय की संभावना तलाश रहे हैं जिससे कि वे तेजी से अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। इससे उन्हें कमीशन भुगतान में कटौती की भरपाई सही ढंग से करने में मदद मिलेगी।' कुछ मामलों में, सलाहकार उन भागीदारों पर ध्यान दे रहे हैं जो वित्तीय उत्पादों के वितरण के लिए बड़ी कॉरपोरेट इकाई का निर्माण पहले ही कर चुके हैं। आईएफए ने कहा, 'बाद में, विलय से जुड़े व्यवसायों को निजी इक्विटी निवेशकों को हिस्सेदारी बिक्री के जरिये बेचा जा सकेगा।' *- जश कृपलानी*

एसबीआई शेयर को लेकर उत्साह बरकरार मगर चुनौतियां भी कम नहीं

हंसिनी कार्तिक

ऐसे समय में जब निवेशक सरकार नियंत्रित इकाइयों के शेयरों पर दांव लगाने से कन्नी काट रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक अपवाद साबित हुआ है। सरकारी बैंकों में एसबीआई का शेयर निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। वास्तव में ब्लूमबर्ग ने 54 विश्लेषकों से बात की, जिनमें 51 (94 प्रतिशत) ने शेयर पर दांव लगाने की सिफारिश की। इससे पहले 2005 में 92 प्रतिशत विश्लेषकों ने एसबीआई पर दांव लगाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो एसबीआई शेयर को लेकर निवेशकों का उत्साह उस स्तर पर जा पहुंचा है, जो पहले कभी नहीं दिखा था। हालांकि, इसके साथ ही निवेशकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि मौजूदा कमजोर हालात में शेयर अपनी रफ्तार कायम रखने में कितना सफल रह पाएगा।

चालू वित्त वर्ष के शुरू से ही हालात एसबीआई के पक्ष में दिखने शुरू हो गए थे। दिसंबर तिमाही के परिणाम ने निवेशकों का विश्वास इस शेयर को लेकर और पुख्ता कर दिया। इस अवधि में बैंक का सकल एवं शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 6.94 प्रतिशत और 2.65 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया। प्रावधान के मद में रकम घटने से घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन इस दौरान सालाना आधार पर 70 आधार अंक की बढ़ोतरी के साथ 3.6 प्रतिशत हो गया और मुनाफा वित्त वर्ष 2016 के बाद से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

ऋण आवंटन में वृद्धि के आंकड़े 7.4 प्रतिशत के साथ भले ही उत्साहवर्द्धक नहीं लग रहे हैं, लेकिन सालाना आधार पर खुदरा ऋण आवंटन 17.5 प्रतिशत के स्तर पर शानदार रहा है। इतना ही नहीं, तीसरी तिमाही में कुल ऋण आवंटन में खुदरा

हालांकि बैंक के लिए कुछ चिंताएं भी हैं। दूरसंचार कंपनियों को आवंटित ऋण भी चिंता का सबब बन सकता है

ऋण की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत के साथ सर्वोच्च स्तर पर रही। कहा जा सकता है कि तीसरी तिमाही में एस्सार स्टील से 12,000 करोड़ रुपये की वसूली से खासी राहत मिली, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एसबीआई ने तीसरी तिमाही में बेहतरीन प्रयास किए हैं।

हालांकि बैंक के लिए कुछ नई चिंताए भी हैं। अगर दीवान हाउसिंग के कारण एसबीआई को 16,500 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं करना होता तो तीसरी तिमाही के आंकड़े और भी अच्छे होते। कुल मिलाकर ऋण के एनपीए में तब्दील होने की दर दूसरी तिमाही के 1.71 प्रतिशत से बढ़कर 3.75 हो गई।

दूरसंचार कंपनियों को आवंटित ऋण भी चिंता का सबब बन सकता है। जे पी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार वोडाफोन आइडिया को आवंटित 16,000 करोड़ रुपये परेशानी पैदा कर सकता है। जेपी मॉर्गन के अनुसार एसबीआई शेयर को दी गई 'खरीद' रेटिंग के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। इस बीच, आर्थिक हालात में सुधार के संकेत नहीं मिलने से एसबीआई के लिए आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि देश में ज्यादातर कंपनियों को उसने कर्ज दे रखा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषकों का कहना है कि आकर्षक मूल्यांकन के बावजूद बाहरी कारकों से चुनौतियां बरकरार हैं। विश्लेषकों का कहना है, 'निवेशकों की सतर्कता समझी जा सकती है। हमें उम्मीद है कि इन सभी चुनौतियों से समय से पहले निपट लिया जाएगा।'

एसबीआई को बाजार से खासा समर्थन मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बैंक ने अपने ऊपर दबाव काफी हद तक कम कर लिया है। अब उसे एनपीए नियंत्रित करने के लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। एनपीए बढ़ने की हालत में इस शेयर को लेकर निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है।

आकर्षक दांव है एसबीआई काड्र्स

श्रीपाद ऑटे

सूचीबद्धता के तीन महीने के अंदर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने जिस तरह शानदार प्रतिफल दिया, उसके बाद बाजार एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज (एसबीआई काड्र्स) के आईपीओ को लेकर भी काफी उम्मीदें कर रहा है। मजबूत बुनियादी आधार के साथ साथ शानदार वृद्धि की संभावना और आकर्षक रिटर्न की आस के कारण महंगे मूल्यांकन के बावजूद यह आईपीओ अच्छा दांव बन गया है। यह आईपीओ 2 मार्च को खुल रहा है।

45-46 गुना पीई और 15 गुना की पीबी वैल्यू (अप्रैल-दिसंबर 2019 के सालाना आंकड़ों पर आधारित) के साथ इसका मूल्यांकन वैश्विक क्रेडिट कार्ड प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले महंगा है और घरेलू ऋणदाताओं के मुकाबले भी ऊंचा है। इक्विरस सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष रोहन मंडोरा का कहना है, 'एसबीआई काड्र्स के विशेष बिजनेस मॉडल, मजबूत वृद्धि संभावना और आकर्षक प्रतिफल अनुपात ने महंगे मूल्यांकन को तर्कसंगत साबित किया है।' 'खरीद' रेटिंग दे चुके नारनोलिया फाइनैंशियल एडवाइजर्स के विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ऊंची आय वृद्धि महंगे मूल्यांकन को सही ठहराती है। नवंबर 2019 तक कार्डों की संख्या के लिहाज से एसबीआई काड्र्स की 18 प्रतिशत बाजार भागीदारी रही है। वित्त वर्ष 2015-19 से क्रेडिट कार्डों में उसकी बढ़ोतरी 27 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर से हुई। इससे कंपनी को बाजार भागीदारी में 300 आधार अंक की तेजी दर्ज करने में मदद मिली।

■ नवंबर 2019 तक कार्डों की संख्या के लिहाज से बाजार में एसबीआई काड्र्स की 18 प्रतिशत भागीदारी थी

कुल क्रेडिट कार्ड खर्च में अच्छी तेजी, अपनी पैतृक (एसबीआई) से ग्राहकों के आने, और लागत किफायत (वित्त वर्ष 2017-19 के दौरान लागत-आय अनुपात 204 आधार अंक तक घटा) से एसबीआई काड्र्स को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने में मदद मिली है। कुल परिचालन आय और राजस्व वित्त वर्ष 2017-19 के दौरान 41 से 45 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ा और वित्त वर्ष 2020 के पहले 9 महीनों में इनमें सालाना आधार पर 35 प्रतिशत और 84 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ। दो वर्षों के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिफल 80 आधार अंक तक सुधरकर वित्त वर्ष 2019 में लगभग 5 प्रतिशत दर्ज किया गया।

मजबूत पहुंच, शानदार को-ब्रांडिंग रणनीति और एसबीआई के नए ग्राहक आधार से वृद्धि की रफ्तार तेज करने में मदद मिलेगी

मजबूत वृद्धि और शानदार प्रतिफल अनुपात का रुझान बरकरार रहने की संभावना है। धीमी कार्ड पहुंच (विकसित देशों में प्रति 100 लोगों पर 30 के मुकाबले भारत में प्रति 100 लोगों पर महज 3-4 कार्ड) से खुदरा ऋण वृद्धि अब मजबूत रहने की संभावना है और डिजिटलीकरण भी घरेलू क्रेडिट कार्ड उद्योग के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। क्रिसिल रिसर्च के अनुमानों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खर्च वित्त वर्ष 2015-19 के दौरान 32 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर के साथ बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था और वित्त वर्ष 2024 तक इसके 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। अनुकूल वृहद परिदृश्य के अलावा, छोटे और मझोले इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने, मजबूत पहुंच, शानदार को-ब्रांडिंग रणनीति और एसबीआई के नए ग्राहक आधार से भविष्य में वृद्धि की रफ्तार में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, मौजूदा समय में कंपनी ने एसबीआई के संभावित ग्राहक आधार (छोटे खातों को छोड़कर) का 10 प्रतिशत हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है।

कई संभावित जोखिम भी हैं, जिनमें यूपीआई जैसे अन्य डिजिटल चैनलों से प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से शामिल है। हालांकि, इक्रा के सेक्टर हेड (वित्त क्षेत्र-रेटिंग्स) अनिल गुप्ता का कहना है कि क्रेडिट कार्ड बाजार के अन्य डिजिटल माध्यमों की वजह से प्रभावित होने की आशंका कम है, क्योंकि इनका इस्तेमाल अक्सर छोटे आकार के लेनदेन में किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऊंची राशि के लेनदेन में किया जा सकता है।

निवेशकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। एमके ग्लोबल के आनंद दामा और नीलम भाटिया का कहना है, 'कमजोर आर्थिक एवं रोजगार रुझानों की वजह से परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम बढ़ रहा है। एसबीआई काड्र्स को ऊंची भुगतान चूक दर का सामना करना पड़ रहा है और उसका सकल एनपीए अनुपात दूसरी तिमाही के 2.3 प्रतिशत के मुकाबले 2.47 प्रतिशत रहा, जिसे देखते हुए सतर्क रहने की भी जरूरत है।'

मंदी या संकट की वजह से कुछ एशियाई देशों (हॉन्गकॉन्ग, ताइवान आदि) में भी क्रेडिट कार्ड भुगतान में चूक के मामले बढ़ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस वजह से, परिसंपत्ति गुणवत्ता में किसी तरह की गिरावट से मूल्यांकन पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि वेतनभोगी ग्राहकों की ऊंची भागीदारी (85 प्रतिशत से अधिक) से कुछ राहत मिली है। कुल मिलाकर, यह निर्गम दीर्घावधि परिदृश्य से निवेशकों के लिए अच्छा दिख रहा है।

बीएस बातचीत

अगर झटके नहीं लगे तो बाजार अच्छा प्रदर्शन करेगा

बाजार के लिए 2020 अब तक आकर्षक रहा है। हीलियस कैपिटल के संस्थापक एवं फंड प्रबंधक **समीर अरोड़ा** ने **पुनीत वाधवा** के साथ साक्षात्कार में बताया कि भविष्य में वोडाफोन आइडिया के दिवालिया होने जैसे झटके न लगें, तो इक्विटी बाजार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। पेश है बातचीत के अंशः

अगले 6 महीनों में बाजार की चाल कैसी रहेगी?

बाजार अभी उचित स्तर पर दिख रहा है। प्रमुख सूचकांकों ने पिछले दो वर्षों से दमदार प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार उन शेयरों के लिहाज से दायरा बढ़ा रहे हैं, जो हाल के वर्षों में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यावसायिक परिदृश्य सुधारने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों से असंगठित और छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। नोटबंदी से छोटी कंपनियां प्रभावित हुई हैं। इन कंपनियों की बिक्री/लागत/ कार्यशील पूंजी व्यवस्था नकदी पर आधारित रही है। इसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छोटी कंपनियों के लिए कर चोरी करना मुश्किल हुआ है, क्योंकि बड़ी कंपनियां पहले से ही करों के प्रति सजग बनी हुई हैं। रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट, यानी रेरा से छोटे डेवलपर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि समय पर परियोजना पूरी करने को लेकर उनकी क्षमता पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। इसके अलावा 2017 में मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों में भारी तेजी बेहतर परिदृश्य पर नहीं बल्कि म्युचुअल फंडों में घरेलू पूंजी प्रवाह में वृद्धि की वजह से आई थी। यदि आगामी झटके (वोडाफोन आइडिया के दिवालिया होने जैसे) न लगें, तो इक्विटी बाजार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

क्या कोरोनावायरस का खतरा घट रहा है या अभी बिकवाली का एक और दौर आ सकता है?

मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि बाजार कोरोनावायरस के प्रभाव को समझ चुका है और बाजार में किसी तरह की अनिश्चितता या बड़ा जोखिम पैदा नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर, आप बाजार में इस समय गिरावट की आशंका जता सकते हैं और समस्या घटने से सुधार देख सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में, बाजार अंतरिम नकारात्मक स्थिति की चिंता किए बगैर सकारात्मक परिदृश्य की ओर बढ़ सकते हैं। बाजारों द्वारा स्थिति के इस विश्लेषण का मतलब है कि वह कोरोनावायरस के शुरुआती चरण पर दांव लगा रहे हैं।

क्या आप मानते हैं कि चीन में कोरोनावायरस फैलने से भारत को कोई मदद मिलेगी?

यदि निवेशक और कंपनियां यह निर्णय लेती हैं कि उन्हें अपना ज्यादातर निवेश चीन में नहीं करना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से भारत पर जोर देना चाहिए, तो भारत को कुछ फायदा हो सकता है। नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट करों में कटौती कर सरकार ने अमेरिका-चीन व्यापारिक टकराव के दौर में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में नई शुरुआत की। कोरोनावायरस से इन निर्णयों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।

विदेशी निवेशक भारत को किस नजरिये से देख रहे हैं?

विदेशी पूंजी प्रवाह के लिहाज से पिछला वर्ष भारत के लिए अच्छा रहा, भले ही बाजार ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी हद तक कमजोर प्रदर्शन किया। एक स्तर पर, भारत वैश्विक, उभरते और एशियाई बाजारों में आने वाले प्रवाह का हिस्सा है और उसे उसकी उचित हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें बड़ा प्रवाह आकर्षित करने और लगातार काम करने की जरूरत होगी।

क्या कॉरपोरेट करों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी?

इस कर कटौती से उद्योगों का भरोसा बढ़ा है और साथ ही संकेत मिला है कि सरकार ने कॉरपोरेट सेहत पर ध्यान दिया है। मेरा मानना था कि सरकार उपभोक्ताओं को कर रियायत का लाभ देगी, लेकिन धीमी जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय चुनौतियों के कारण सरकार के फिलहाल इस दिशा में आगे बढ़ने की कम ही गुंजाइश है।

क्या 2020 मिड- और स्मॉल-कैप का वर्ष हो सकता है?

मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों ने पिछले दो वर्षों के दौरान कमजोर प्रदर्शन किया है। इसलिए यह तर्क उचित है कि इन शेयरों का समय जल्द आएगा। दूसरी तरफ, 2017 में इन शेयरों में तेजी को पूरी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह तेजी नोटबंदी के बाद घरेलू म्युचुअल फंडों में भारी प्रवाह से आई। कुल मिलाकर सभी सेगमेंट के फंडों में अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें और बेहतर परिदृश्य की उम्मीद रखें।

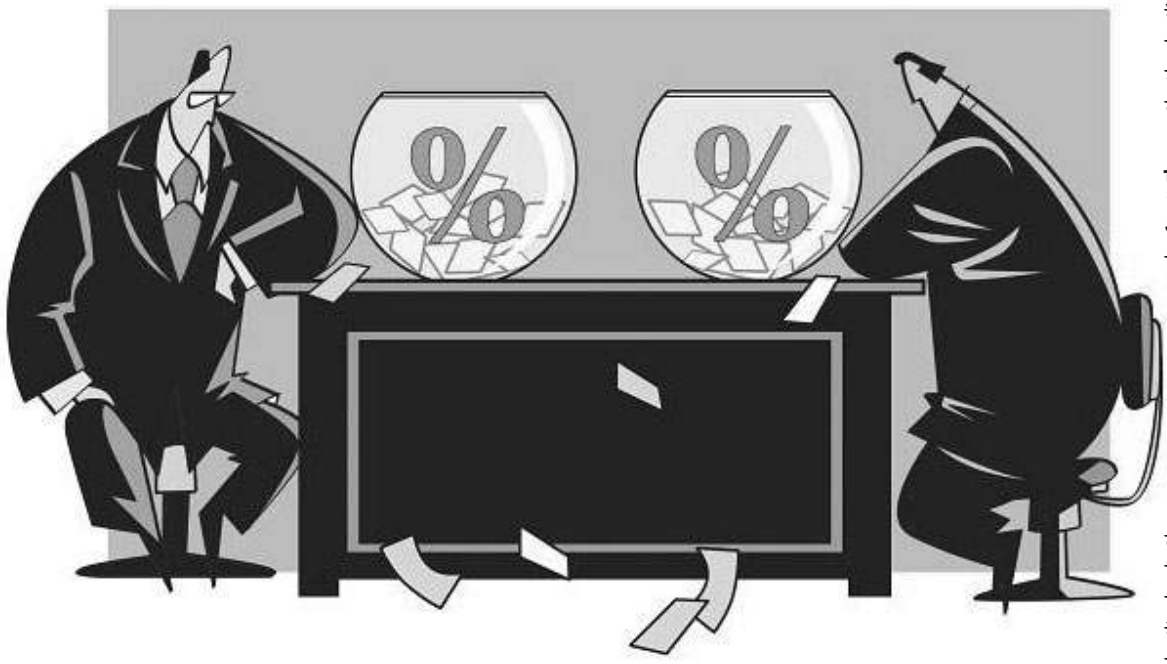

पुरानी और नई कर प्रणाली में कौन सटीक

जिन लोगों की आयकर कटौतियां एक निश्चित स्तर से ऊपर जाती हैं तो पुरानी कर प्रणाली में बने रहना होगा बेहतर

संजय कुमार सिंह और बिंदिशा सारंग

मुंबई की एक विज्ञापन एजेंसी में खाता विशेषज्ञ ने नाम प्रकाशित नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि वह भविष्य में इस शहर में एक घर खरीदना चाहती हैं। उनकी उम्र 30 साल से अधिक है और इस समय उनका वेतन 6.05 लाख रुपये है। वह सभी संभावित कर छूट लेना चाहती हैं, इसलिए वह वित्त मंत्री द्वारा 2020 के बजट में शुरू की गई नई रियायती कर प्रणाली को नहीं अपनाना चाहती हैं। इसके बावजूद वह यह जानना चाहती हैं कि अधिक कर दरों वाली पुरानी प्रणली या कम दरों मगर बिना छूट वाली नई कर प्रणाली में से कौन सी उनके लिए बेहतर रहेगी।

नई और पुरानी कर प्रणाली के फायदे

- नई कर प्रणाली का लाभ यह है कि इसमें पुरानी कर प्रणाली की तुलना में रियायती कर दरें मुहैया कराई गई हैं
- नई कर प्रणाली से करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा
- करदाताओं को पुरानी कर प्रणाली के तहत छूट हासिल करने के लिए निवेश और खर्च के सबूत देने होंगे
- नई कर प्रणाली में वे इन सब दिक्कतों से बच जाएंगे
- पुरानी कर प्रणाली उन कुछ योजनाओं में निवेश करने के लिए बाध्य करती है, जिन पर छूट हैं
- नई कर प्रणाली को अपनाने वाले करदाता इस मापदंड के आधार पर योजनाएं चुन सकेंगे कि उनसे संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी या नहीं
- नई कर प्रणाली को अपनाने में 75,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है

आसान प्रणाली

नई कर प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें पुरानी कर प्रणाली की तुलना में रियायती कर दरें मुहैया कराई गई हैं। पीएसएल एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसिटर्स में संस्थापक और प्रबंध साझेदार समीर जैन ने कहा, 'पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आय के लिए 10 फीसदी की नई कर श्रेणी शुरू की गई है और पहले की कर दरों को भी घटाया गया है।' नई कर प्रणाली से करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा।

करदाताओं को पुरानी कर प्रणाली के तहत छूट हासिल करने के लिए निवेश और खर्च (रीइंबर्समेंट के मामले में) के सबूत देने होंगे। लेकिन वे नई कर प्रणाली में इन सब दिक्कतों से बच जाएंगे। आरएसएम एसट्यूट कंसल्टिंग ग्रुप के संस्थापक सुरेश सुराणा ने कहा, 'इसमें कम दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिससे कर भरना आसान हो गया है।' पुरानी कर प्रणाली करदाताओं को उन कुछ योजनाओं में निवेश करने के लिए बाध्य करती है, जिन पर छूट उपलब्ध हैं। इनमें से सभी संपत्ति को बढ़ाने में सबसे बेहतर विकल्प नहीं हैं। पर्याप्त वित्तीय ज्ञान नहीं रखने वाले बहुत से करदाताओं को ऐसी योजनाएं बेच दी जाती हैं, जिनसे उन्हें कर बचाने में तो मदद मिलती है मगर बहुत लंबी अवधि में भी कमजोर प्रतिफल मिलता है।

नई कर प्रणाली को अपनाने वाले करदाता इस मापदंड के आधार पर योजनाएं चुन सकेंगे कि उनसे संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी या नहीं। कर बचत वाली सभी योजनाओं में निवेश को बनाए रखने का एक निश्चित समय (लॉक इन) होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में लॉक इन 15 साल है। पांच वर्षीय कर बचत वाली सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में लॉक-इन पांच साल है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस) में लॉक-इन तीन साल है। नई कर प्रणाली को अपनाने वाले करदाताओं को यह फायदा होगा कि वे ऐसी योजनाओं में निवेश के बाद कभी भी अपना पैसा निकाल सकेंगे।

नई कर प्रणाली का दूसरा पक्ष यह है कि करदाताओं को वे सभी छूट नहीं मिल पाएंगी, जो पुरानी कर प्रणाली के तहत उपलब्ध हैं। इनमें से एक छूट धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की उपलब्ध है। वहीं धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में 50,000 रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 24 के तहत आवास ऋण ब्याज पर दो लाख रुपये की छूट मिलती है। नई कर प्रणाली में एनपीएस में नियोक्ता के योगदान जैसी कुछेक कर छूट ही मिल पाएंगी।

नई कर प्रणाली को अपनाने में 75,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। सुराणा ने कहा, 'कंपनी रियायती कर प्रणाली में सभी आय स्तरों पर कर की दरों में कमी की गई है, लेकिन इससे इतर व्यक्तिगत रियायती कर प्रणाली का दायरा सीमित है। उच्च कर वर्ग में आने वाले लोगों के लिए कर की प्रभावी दर आगे भी 42.7 फीसदी बनी रहेगी।'

पुरानी कर प्रणाली के तहत अधिकतम कर लाभ संभव

पुरानी प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि कर्मचारी के वेतन का ढांचा इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि वह अधिकतम आय कटौतियां हासिल कर सके और कर बचा सके। किराये पर रहने वाले लोगों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) के तहत आय कटौती मिलती है। बहुत से करदाता चार साल में दो बार अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाते हैं ताकि लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) हासिल किया जा सके। पुरानी कर प्रणाली बचत एवं निवेश की संस्कृति कायम करने में मददगार है। क्लियरटैक्स के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा, 'लोग पीपीएफ जैसी योजनाओं में निवेश करके कर बचत को लंबी अवधि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोष बनाने से जोड़ देते हैं।'

दूसरी ओर पुरानी कर प्रणाली ज्यादा जटिल है और इसके तहत उपलब्ध लाभों को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कुछ समझ होनी जरूरी है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कर बचत वाली योजनाओं में लॉक-इन होता है। सुराणा ने कहा, 'वरिष्ठ नागरिकों जैसे लोग अपने हाथ में पैसा रखने को तरजीह दे सकते हैं।' पुरानी कर प्रणाली में यदि करदाता को कर अधिकारियों द्वारा आकलन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें निवेश के सबूत रखने पड़ते हैं।

आपको क्या करना चाहिए?

दोनों ही प्रणालियों की अपनी-अपनी खूबियां हैं। ऐसे युवा करदाता, जो कर बचत वाली योजनाओं में निवेश के झंझट से बचना चाहते हैं और अपने हाथ में ज्यादा पैसा चाहते हैं, वे नई कर प्रणाली को अपना सकते हैं। अन्य सभी को कोई विकल्प चुनने से पहले सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। गुप्ता ने कहा, 'हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि करदाताओं के लिए विभिन्न आयकर स्तरों पर विभिन्न सीमाएं या ब्रेक ईवन पॉइंट हैं। अगर वे इन स्तरों को पार करते हैं तो पुरानी कर प्रणाली पर बने रहना ज्यादा उचित होगा।'

वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को पुरानी कर प्रणाली के तहत क्रमश: तीन लाख रुपये और पांच लाख रुपये पर अधिक छूट मिलती है। उन्हें अन्य बहुत सी कटौतियों का लाभ मिलता है, जिनमें धारा 80सी, धारा 80डी (स्वास्थ्य बीमा पर 30,000 रुपये), धारा 80 टीटीबी (ब्याज आय पर 50,000 रुपये) आदि शामिल हैं। उन्हें दोनों कर प्रणालियों में से किसी एक को चुनने से पहले अपनी स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। तार्किक और आंकड़ों पर आधारित विकल्प चुनने के लिए आयकर विभाग के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें।

आखिर में यह बात याद रखें कि एक बार किसी प्रणाली को चुनने के बाद व्यक्तिगत करदाता के लिए उसी में बने रहना जरूरी नहीं है। वे हर साल किसी भी प्रणाली को अपना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की कारोबारी या पेशेवर आय है, उन्हें किसी एक को चुनना होगा और उसी में बने रहना होगा।

सोच-समझकर करें एनएफओ में निवेश

बिंदिशा सारंग

कई फंड हाउसों द्वारा नई फंड पेशकश (एनएफओ) लाई जा रही हैं। ऐसे में ज्यादातर निवेशकों के पास इन योजनाओं में निवेश के लिए वितरकों से ईमेल और कॉल आ सकती हैं। यह उन्हें आकर्षित करने की नई बिक्री रणनीति है। मौजूदा समय में, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, टाटा मल्टी ऐसेट अपॉर्च्युनिटीज फंड, और क्लोज-एंडेड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्युरिटी प्लान (एफएमपी) - सीरीज 87 - 1156 डेज प्लान डी अभिदान के लिए खुले हुए हैं। किसी म्युचुअल फंड (एमएफ) के लिए ऐसी नई योजना बेहद महत्वपूर्ण होती है जो नए क्षेत्रों को कवर करती है। हालांकि किसी एनएफओ में निवेश से पहले निवेशकों को योजना से जुड़ी मूल्य वृद्धि के बारे में समझ लेना चाहिए। इसके लिए इन कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

फंड पर नजर रखें

- क्लोज-एंडेड योजना हो या ओपन-एंडेड, हर साल फरवरी और मार्च के आसपास कई फंड हाउस कर लाभ को देखते हुए 13-15 महीने के एफएमपी पेश करते हैं
- वित्त वर्ष के अंत में एफएमपी पेश कर, ये फंड हाउस निवेशकों को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए क्लेम इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लाभ में मदद करते हैं
- अपने निवेश पर नियमित रूप से नजर नहीं रख पाने वाले छोटे निवेशकों को पैसिव फंडों की निवेश रणनीति पर अमल करना चाहिए और इंडेक्स फंडों से जुड़े रहना चाहिए

अच्छा रिकॉर्ड

हालांकि पिछले प्रदर्शन से भविष्य का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी निवेश करते वक्त पिछले रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सृजन फाइनैंशियल एडवायजर्स एलएलपी में संस्थापक पार्टनर दीपाली सेन कहती हैं, 'मौजूदा ओपन-एंडेड फंडों का कई वर्षों का पिछला रिकॉर्ड होता है। एनएफओ का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए पिछले प्रदर्शन की समीक्षा नहीं की जा सकती।'

इसमें निवेश का निर्णय इस आशंका से जुड़ा रहेगा कि योजना अच्छा प्रदर्शन करेगी या नहीं। याद रखें, फंड हाउस की अन्य योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सिर्फ इसलिए यह जरूरी नहीं है कि नई फंड पेशकश भी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

योजना का लक्ष्य

हरेक योजना का निवेश लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए, एडलवाइस एमएफ ने एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड पेश किया है। इस फंड का लक्ष्य उन उभरती प्रौद्योगिकियों तक पहुंच उपलब्ध कराना है जिन्हें अमेरिका में शुरुआती स्तर पर अपनाया जा रहा है। इनमें सिनॉप्सिस, टेस्ला, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, एनालॉग डिवाइसेज, सर्विसनाउ मुख्य रूप से शामिल हैं।

> यदि ये योजनाएं आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरी हों तभी इनमें निवेश करें, अन्यथा इनसे बचना समझदारी भरा निर्णय साबित हो सकता है

अन्य उदाहरण टाटा मल्टी ऐसेट अपॉर्च्युनिटीज फंड है जो मुख्य रूप से तीन परिसंपत्ति वर्गों - इक्विटी, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेट में निवेश करेगा।

विवेकतारू के संस्थापक स्वप्निल केंधे कहते हैं, 'एनएफओ में निवेश से पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि क्या फंड आपकी वित्तीय योजना या परिसंपत्ति आवंटन के लिहाज से उपयुक्त है। जब तक एनएफओ में कुछ खासियत न हो और आपकी वित्तीय योजना के अनुरूप न हो, तब तक उसमें निवेश से परहेज किया जाना चाहिए।'

चाहे क्लोज-एंडेड योजना हो या ओपन-एंडेड, याद रखें कि हर साल फरवरी और मार्च के आसपास कई फंड हाउस कर लाभ को देखते हुए 13-15 महीने के एफएमपी पेश करते हैं। वित्त वर्ष के अंत में एफएमपी पेश कर, ये फंड हाउस निवेशकों को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए क्लेम इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लाभ में मदद करते हैं। इसके अलावा, वास्तविक प्रदर्शन एफएमपी पर सांकेतिक प्रतिफल के काफी करीब होगा। जहां कई वित्तीय सलाहकार एनएफओ से दूर रहते हैं, वहीं वे उन निवेशकों के लिए क्लोज-एंडेड एफएमपी की सलाह देते हैं जो प्रतिफल में ज्यादा उतार-चढ़ाव पसंद नहीं करते। केंधे कहते हैं, 'अपने निवेश पर नियमित रूप से नजर नहीं रख पाने वाले छोटे निवेशकों को पैसिव फंडों की निवेश रणनीति पर अमल करना चाहिए और इंडेक्स फंडों से जुड़े रहना चाहिए। निफ्टी-50 और निफ्टी नेक्स्ट फंडों का चयन करें और 80:20 के अनुपात में निवेश करें। यदि आप ऐक्टिव फंडों पर विचार कर रहे हों तो हमेशा अच्छे रिकॉर्ड वाली मल्टी-कैप फंड जैसी मौजूदा योजनाओं को चुनें।'

याद रखें, किसी खास पेशकश में भी छोटे निवेशक उसका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दीपाली सेन कहती हैं, 'इस पर विचार करें कि क्या एनएफओ आपके पोर्टफोलियो में किसी विशेष कमी को पूरा करेगा। अन्यथा, छोटे निवेशकों को एनएफओ से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए।'

बीते साल का प्रदर्शन देखकर ही न कर डालें डेट फंडों में निवेश

आपको निवेश के लिए उन फंडों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जो क्रेडिट और अवधि जोखिम से बचते हैं

संजय कुमार सिंह

- पिछले साल डेट फंडों में में लंबी अवधि के फंडों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, जिन्होंने औसतन 12.13 फीसदी प्रतिफल दिया
- इस साल बाजार की स्थितियां बदलने से आपको इन फंडों में नुकसान हो सकता है
- खुदरा निवेशकों को डेट फंड का पोर्टफोलियो बनाते समय युक्तिपूर्वक सोचने के बजाय परिसंपत्ति आवंटन मॉडल अपनाना चाहिए
- इस समय यह निश्चित नहीं है कि लंबी अवधि में ब्याज दरें किस दिशा में जाएंगी, इसलिए निवेशकों को अवधि के जोखिम लेने से बचना चाहिए

म्युचुअल फंडों की किसी भी श्रेणी में बीते वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर निवेश करना नुकसान की रणनीति मानी जाती है। लेकिन यह डेट फंडों में विशेष रूप से नुकसानदेह है। पिछले साल डेट फंडों में में लंबी अवधि के फंडों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, जिन्होंने औसतन 12.13 फीसदी प्रतिफल दिया। हालांकि अगर आप भी ऐसा प्रतिफल हासिल करने के लिए इस श्रेणी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अपना विचार त्याग दें। बाजार की स्थितियां बदलने से आपको इन फंडों में नुकसान हो सकता है।

दरों की दिशा अनिश्चित

ब्याज दरें किस दिशा में जा रही हैं, इसे लेकर आज फंड प्रबंधकों के अलग-अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि लंबी अवधि के बॉन्डों का प्रतिफल 2020 में बढ़ने जा रहा है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में मुख्य निवेश अधिकारी (फिक्स्ड इनकम) मनीष डांगी ने कहा, 'वैश्विक और घरेलू स्तर पर वृद्धि में सुधार आ रहा है और महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए 10 साल के सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल अगली तीन-चार तिमाहियों में बढ़कर 7 फीसदी के आसपास पहुंच सकता है, जो इस समय करीब 6.6 फीसदी है।'

अन्य डेट फंड प्रबंधकों का मानना है कि लंबी अवधि के बॉन्डों पर प्रतिफल में नरमी कुछ समय और बनी रह सकती है। आईडीएफसी एएमसी के प्रमुख (निश्चित आय) सुयश चौधरी ने कहा कि इस समय अवधि का अंतर (एक साल और लंबी अवधि के बॉन्डों के प्रतिफल में अंतर) बहुत अधिक है। वह कहते हैं, 'केवल मूल्यांकन के लिहाज से लंबी अवधि के बॉन्ड आकर्षक नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अवधि के अंतर को लक्षित करने वाले टूल का उपयोग जारी रखता है और सरकार मध्यम अवधि में उधारी की खातिर विदेशी पूंजी लाने के किसी खाते को पेश करती है तो लंबी अवधि के बॉन्डों को लेकर नजरिया कम से कम कुछ महीनों तक सकारात्मक बना रहेगा। लेकिन अगर आरबीआई कुछ महीनों बाद इस रणनीति को वापस ले लेता है तो इन बॉन्डों में उतार-चढ़ाव आ सकता है।'

साफ तौर पर ऐसे माहौल में जहां इस बारे में कोई सहमति नहीं है कि ब्याज दरें किस दिशा में जा रही हैं तो खुदरा निवेशकों को सबसे पहले सुरक्षा के सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए।

मिंटवॉक के सह-संस्थापक निखिल बनर्जी ने कहा, 'खुदरा निवेशकों को इक्विटी फंडों में जोखिम लेना चाहिए और अपने डेट फंड के पोर्टफोलियो से सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।'

आवंटन मॉडल को अपनाएं

खुदरा निवेशकों को डेट फंड का पोर्टफोलियो बनाते समय युक्तिपूर्वक सोचने के बजाय परिसंपत्ति आवंटन मॉडल अपनाना चाहिए। चौधरी ने सुझाव दिया कि निवेशक पोर्टफोलियो को तीन हिस्सों- लिक्विडिटी, कोर और सैटेलाइट बकेट में बांटें। लिक्विडिटी बकेट नकदी प्रबंधन के लिए होना चाहिए। इसके लिए लिक्विड और ओवरनाइट फंडों में निवेश किया जाना चाहिए। निवेशक के निश्चित आय आवंटन में बड़ा हिस्सा कोर बकेट का होना चाहिए, भले ही वित्तीय बाजार किसी भी चक्र में हों।

चौधरी ने कहा, 'कोर निवेश की खूबी यह होनी चाहिए कि इसमें क्रेडिट और अवधि का जोखिम सामान्य होना चाहिए।' इस श्रेणी में वे फंड आएंगे, जो 4-5 साल की अवधि वाले एएए और सॉवरिन बॉन्डों में निवेश करते हैं। इसमें मनी मार्केट से लेकर लघु से मध्यम अवधि के फंड शामिल होंगे।

आखिर में सैटेलाइट बकेट है। इसमें क्रेडिट और अवधि का जोखिम अधिक हो सकता है, लेकिन इसमें आवंटन का शेष या छोटा हिस्सा रखा जाना चाहिए। अगर निवेशक क्षमता रखता है तो वह थोड़ा अवधि या क्रेडिट जोखिम ले सकता है। वह सक्रिय रूप से प्रबंधित डायनेमिक बॉन्ड फंड में निवेश कर सकता है, जिसने पिछले 10 से 15 वर्ष में लगातार ब्याज दर चक्र को लगातार प्रबंधित करने में अपनी क्षमता को साबित किया है। निवेशक अपने धन का करीब 10 से 15 फीसदी हिस्सा लिक्विड बकेट में लगा सकते हैं। वही 60 फीसदी पैसा कोर बकेट में और 20 फीसदी पैसा सैटेलाइट बकेट में लगाया जा सकता है।

अवधि और क्रेडिट जोखिम से बचें

इस समय यह निश्चित नहीं है कि लंबी अवधि में ब्याज दरें किस दिशा में जाएंगी, इसलिए निवेशकों को अवधि के जोखिम लेने से बचना चाहिए। बनर्जी ने कहा, 'ऐसे पुराने निवेशक, जिन्हें वृहद अर्थव्यवस्था की समझ है या जो सलाहकार की सेवाएं लेते हैं, उन्हें ही अवधि का जोखिम लेना चाहिए। ज्यादातर खुदरा निवेशकों को लंबी अवधि के फंडों से दूर रहना चाहिए।' अगर लंबी अवधि के बॉन्डों के प्रतिफल में इजाफा होता है तो उन्हें इन फंडों में घाटा हो सकता है।

ऋण के लिहाज से बाजारों में पिछले डेढ़ साल के दौरान बड़ा उठापटक रही है। अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, इसलिए कर्ज की स्थिति ठीक नहीं है। ऋण लौटाने में डिफॉल्ट करने की और घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह निवेशकों के लिए क्रेडिट रिस्क फंड जैसी अधिक प्रतिफल वाली रणनीतियां अपनाने को उपयुक्त समय नहीं है। गौरतलब है कि क्रेडिट रिस्क फंड कम रेटिंग वाले बॉन्डों में निवेश करते हैं।

सुरक्षित जगह

इस समय कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी बॉन्डों के बीच अंतर अधिक है। अगर नकदी की स्थिति ऊंचे स्तरों पर बनी रहती है तो एएए और एए रेटिंग प्राप्त एक से तीन साल के कॉरपोरेट बॉन्डों पर प्रतिफल थोड़ा और कम हो सकता है। डांगी ने कहा, 'उन फंडों में निवेश करें, जो एक से तीन साल की अवधि वाले एएए और एए रेटिंग प्राप्त बॉन्डों में निवेश करते हैं। एक साल के लिए निवेश करने वाला व्यक्ति कम अवधि के फंड में निवेश कर सकता है, जबकि दो से तीन साल के लिए निवेश करने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड फंड को चुन सकते हैं।' कॉरपोरेट बॉन्ड फंड का गुणवत्तायुक्त पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिनका निवेश मुख्य रूप से एएए रेटिंग प्राप्त सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में होना चाहिए।

केवल मार्जिन पर लें जोखिम

बहुत सी कंपनियों ने कम नकदी और आर्थिक मंदी दोनों स्थितियां झेली हैं। इस उठापटक के दौर में भी उनके बॉन्डों की रेटिंग एए रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली कुछ तिमाहियों में हालात कठिन होने के बावजूद उनके बॉन्डों की रेटिंग कम नहीं हुई है। ये ऐसी कंपनियां हैं, जिनका बाजार में दबदबा है और उन पर अत्यधिक कर्ज भी नहीं है। उनके पास अच्छा प्रबंधन भी है। डांगी का सुझाव है कि ऐसे फंड चुनें, जो इन बॉन्डों में निवेश करते हों। आम तौर पर पीएसयू क्षेत्र में एएए रेटिंग प्राप्त दो से तीन साल की अवधि वाले बॉन्डों का प्रतिफल करीब 6.50 से 6.75 फीसदी बना हुआ है। ये एए रेटिंग प्राप्त बॉन्ड 8.5 से 9 फीसदी प्रतिफल दे रहे हैं, इसलिए निवेशक दो प्रतिशत अधिक प्रतिफल अर्जित कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। इस चीज के लिए तैयार निवेशक डायनेमिक बॉन्ड फंडों में निवेश कर सकते हैं।

कोरोना: होली के खिलौने महंगे

कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से चीन से आपूर्ति में बाधाएं बढ़ गई हैं

समरीन अहमद

कोरोनावायरस के फैलने की वजह से अंतरराष्ट्रीय कारोबार को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और ऐसे में संभव है कि होली का त्योहार भी फीका-फीका ही रहे हैं। दरअसल होली में इस्तेमाल होने वाली पिचकारी और वॉटर गन की कीमतों में 20 फीसदी तक की तेजी दिखने के आसार बन रहे हैं क्योंकि चीन से आपूर्ति में बाधाएं दिख रही हैं। उद्योग के मुताबिक देश में होली से संबंधित 90 फीसदी खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। कोरोनावायरस की महामारी फैलने से काफी पहले नवंबर में बड़े वितरकों ने अग्रिम तौर पर ही अपना ऑर्डर दे दिया था। ऐसे में छोटे कारोबारियों की बिक्री पर ज्यादा असर पड़ेगा। देश में छोटे कारोबार के लिए ऑनलाइन बी2बी पोर्टल ट्रेडइंडिया डॉट कॉम के मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप छेत्री ने कहा, 'विनिर्माता अपने उत्पाद की कीमतों में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं क्योंकि आपूर्ति के मुकाबले मांग ज्यादा है। छोटे कारोबारी पिछले साल के ही स्टॉक को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि वे घाटे में न रहें।' छेत्री ने कहा कि दिसंबर से ही छोटे स्तर के कारोबारियों की तरफ से पोर्टल पर होली के सामान की पूछताछ में 127 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि वे स्टॉक खरीदना चाहते थे। ऑर्गेनिक रंग की मांग में भी करीब 23 फीसदी तक की तेजी देखी गई है खासतौर पर मेट्रो शहरों में। कई कारोबारी भारत पहुंच चुके अपने माल के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के खिलौना वितरक एकेबी कॉरपोरेशन के अनिल काबरा कहते हैं, 'हमने नवंबर में जिस माल के लिए ऑर्डर दिया था वह भारत पहुंच चुका है लेकिन इसके जारी होने में अभी वक्त लग रहा है। हालांकि अगर सबकुछ ठीक रहा तब अगले 3-4 महीने में हमारी बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा।'

- **पिचकारी और वॉटर गन की कीमतों में 20 फीसदी तक की तेजी के दिख रहे आसार**
- **होली से संबंधित 90 फीसदी खिलौने चीन से होते हैं आयात**
- **बड़े कारोबारियों ने नवंबर में ही दे दिया था ऑर्डर लेकिन छोटे कारोबारियों पर दिखेगा असर**

वैश्विक बाजार की शोध कंपनी आईएमएआरसी के मुताबिक घरेलू खिलौना बाजार करीब 1.5 अरब डॉलर का है जो भविष्य में 2024 तक 3.3 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है। इसमें 2019-2024 के दौरान 13.3 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से वृद्धि का अनुमान है। देश में बिकने वाले कुल खिलौने में से मुख्यतौर पर करीब 85 फीसदी चीन से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी और हॉन्गकॉन्ग से खिलौने आयात किए जाते हैं। इसके पहले सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश वायरल हो रहा था कि भारत सरकार ने चीन में बने होली के सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया है जिससे ग्राहकों में खरीदने का जोश कम हो रहा है। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि की गई थी कि ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तुओं और कच्चे माल की आपूर्ति बाधित रहने से खुदरा विक्रेताओं पर असर दिखता रहेगा क्योंकि चीन में संक्रमण के नए मामले की तादाद घटी है। रिटेल इनसाइट्स के संस्थापक विष्णु गुल्लीपल्ली का कहना है, 'घरेलू मांग में मंदी छाई है और उपभोक्ता खर्च को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि कारोबारी सामान मंगाने के लिए वैकल्पिक रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे मांग में तेजी आएगी।'

मदद के लिए तैयार एडीबी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कोरोनावायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को 40 लाख डॉलर (करीब 29 करोड़ रुपये) की मदद देगा। एडीबी ने कोरोनावायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए फरवरी की शुरुआत में 20 लाख डॉलर की मदद देने की घोषणा की थी। बाद में फरवरी के अंत में एडीबी ने 20 लाख डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की। यह राशि एडीबी के सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी। एडीबी ने कहा कि यह मदद आपातकालीन सामान व उपकरण खरीद, भविष्य में प्रतिरोध बनाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था तथा आकलन

कई देशों में सभाओं पर लगा प्रतिबंध

रॉयटर्स

यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका में बड़ी सभाओं तथा सम्मेलन और यात्रा पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि दुनिया भर में कोरोनावायरस के प्रसार डर फैल रहा है। अमेरिका ने शनिवार को कोरोनावायरस संक्रमण से एक मौत के होने की पुष्टि की है। वॉशिंगटन में 50 साल से अधिक उम्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पहले चार मामलों का पता चलने के बाद वॉशिंगटन राज्य में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। अमेरिका के उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, 'हम जानते हैं कि संक्रमण के कुछ और मामले सामने आ सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उन विदेशी नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने पिछले 14 दिन में ईरान की यात्रा की थी। ट्रंप और शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इटली और दक्षिण कोरिया के यात्रियों को सख्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने वायरस प्रभावित इन दो क्षेत्रों में अमेरिकियों को यात्रा न करने की चेतावनी भी दी है। पेंस ने कहा कि ईरान के पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के साथ-साथ अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 14 दिनों में ईरान की यात्रा की होगी तब उन पर भी प्रतिबंध लगा होगा। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका मेक्सिको से लगी दक्षिणी सीमा पर भी यात्रा प्रतिबंध लगा सकता है।

इस महामारी से विमान सेवाओं की मांग में कमी आ रही है और कई विमानन कंपनियों को अपनी सेवाएं रद्द करनी पड़ी या उसमें फेरबदल करना पड़ा। अमेरिकन एयरलाइंस इंक ने शनिवार को कहा कि यह मिलान जाने वाली सेवाएं बंद कर रही है।

इक्वाडोर में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है जबकि मेक्सिको में संक्रमण के चार नए मामलों की पुष्टि हुई है। ब्राजील के अधिकारियों ने देश में दूसरे मामले की पुष्टि की है और यह मरीज हाल में इटली की यात्रा पर गया था। फ्रांस ने 5000 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां 16 नए मामले की पुष्टि हुई है और अब संक्रमित लोगों की कुल तादाद 73 हो गई है। स्विटजरलैंड ने 1000 से अधिक लोगों वाले किसी इवेंट पर प्रतिबंध लगाया है। इटली में भी स्कूल और यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते भी बंद रहेंगे जहां 29 लोगों की मौत हो गई है जबकि संक्रमण के 1,100 से ज्यादा मामले की पुष्टि हुई है।